

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 209 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार, 20 जनवरी 2021, मूल्य रु. 1.50

क्रिकेट टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत

चौथे और अंतिम टेस्ट में आस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराया

ब्रिस्बेन, (एजेंसी)। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत ने आस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने चार मैचों की यह सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। गाबा के मैदान पर पहली बार किसी टीम ने 300 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा किया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आस्ट्रेलिया को उसी की मेजबानी में हराकर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। यह

लगातार दूसरा मौका है जब भारत ने आस्ट्रेलिया को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में मात दी। गाबा स्टेडियम में मिली इस शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी और सर्पाट स्टफ ब्रिस्बेन में तिरंगा फहराते नजर आए। जिस भी भारतीय ने भी इस दृश्य को देखा, उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष और सचिव तेंदुलकर, विराट कोहली ने भी भारत को बधाई दी है। गांगुली ने टवीट करते हुए लिखा, शानदार जीत इसे भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। बीसीसीआई टीम को पांच करोड़ रुपए का बोनस देगी।

जिस भी भारतीय ने भी इस दृश्य को देखा, उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष और सचिव तेंदुलकर, विराट कोहली ने भी भारत को बधाई दी है। गांगुली ने टवीट करते हुए लिखा, शानदार जीत इसे भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। बीसीसीआई टीम को पांच करोड़ रुपए का बोनस देगी।

मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। पीएम ने टवीट कर कहा कि हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम की आस्ट्रेलिया में सफलता पर खुश हैं।



एक नज़र...

आज शपथ लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन

वाशिंगटन, (एजेंसी)। एक राजनीतिक समारोह में 20 जनवरी बुधवार को जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई कमला हैरिस अपने पद की शपथ लेंगी। कोविड-19 की वजह से समारोह में कुछ बदलाव किए गए हैं। मेहमानों की सूची छोटी की गई है और सुरक्षा विंताओं को देखते हुए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 16 जनवरी को उपदिवियों के कैपिटल हिल में घुस जाने की घटना को देखते हुए इस बार ज्यादा पुख्ता इंतजाम होगा। इस दौरान वहा नेशनल गार्ड्स के 10 हजार सैनिक तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त पांच हजार सैनिक उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

4.5 लाख से अधिक लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने के बाद देशभर में अभी तक 454049 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख के आसपास आ गई है। मंत्रालय ने कहा कि सात महीने बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या दो लाख से कम हुई है। वहीं, 8 महीने बाद हर दिन मौतों की संख्या 140 से कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में केवल दो राज्य केरल और महाराष्ट्र ऐसा हैं, जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 50000 से अधिक है।

एयरपोर्ट ठेके को लेकर हुई थी रूपेश की हत्या

पटना, (एजेंसी)। इंडिया एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या एयरपोर्ट पर ठेके को लेकर हुई थी। बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने यह खुलासा करते हुए कहा है कि रूपेश की हत्या एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि इस ठेके को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। डीजीपी ने दावा किया कि पुलिस रूपेश हत्याकांड के खुलासे के करीब है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस इस हत्याकांड के अन्य सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस केस की जांच के बारे में पूरी जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि पुलिस रूपेश हत्याकांड की जांच लगभग पूरी कर चुकी है।

इंडियन ऑयल नरेला में कूड़े से बनाएगी ऊर्जा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दिल्ली के नरेला में कूड़े से ऊर्जा बनाने वाला संयंत्र लगाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मप्र प्रधान, दिल्ली के उपराज्यपाल अमित बैजल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जय प्रकाश और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष एस.एम. वैद्य की मौजूदगी में इंडियन ऑयल ने मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत नरेला के रानीखेड़ा में कूड़े से ऊर्जा बनाने वाला एक एकीकृत संयंत्र लगाने में कंपनी स्थानीय निकाय की मदद करेगी।

सूरत में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को डंपर ने रौंदा, 15 लोगों की मौत

सूरत, (एजेंसी)। गुजरात के शहर सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है। सूरत के पिपलदोड गांव में एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे 18 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।



मृतकों में आठ पुरुष, पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। हादसा देर रात करीब 12 बजे के आसपास हुआ। बताया जा रहा है कि गांव से भरा ट्रक बेहद तेज गति से चल रहा था। गांव के बाबा बूढ़े हुए और फिर सड़क किनारे सो रहे लोगों के लिए काल बन गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार हुए लोग मजदूरी करते थे और सभी राजस्थान के बासवाड़ा जिले के कुशलगाढ़ के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तपतीश शुरू कर दी है। इस हादसे में करीब छह महीने की एक बच्ची बच गई लेकिन दुख की बात है कि बच्ची के साथ ही सो रहे उसके पिता, मां और भाई की मौत हो गई। बच्ची के परिवार में अब सिर्फ एक बहन बची है जो राजस्थान के गांव में है।

ट्रैक्टर रैली पर पीछे हटने को तैयार नहीं किसान, बोले

26 जनवरी को ही होगी दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड

नई दिल्ली ■ एजेंसी

मंगलवार को किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच एक बार फिर बैठक हुई। बैठक 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड को लेकर थी। इससे पहले भी सोमवार को करीब 1 घंटे बैठक चली थी और बैठक का दूसरा दिन मंगलवार को तय हुआ था। मंगलवार को बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी तो मौजूद ही थे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस के भी अधिकारी आए हुए थे। काफी देर चली बैठक के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव ने साफ किया कि किसान परेड तो होनी ही होनी है, अब प्रशासन तय करे कि कैसे होगी।

योगेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के टॉप ऑफिशियल के साथ बातचीत हुई है। तीन बातों पर कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। नंबर 1- किसान गणतंत्र परेड 26 जनवरी को ही निकलेगी। नंबर 2- यह परेड दिल्ली के अंदर होगा। नंबर 3- जो भी जहां से आएंगे उसे प्रशासन सब इसमें हिस्सा लेंगे हमने यह उन्हें आश्वासन दिया है पर पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगी और इससे गणतंत्र और तिरंगे की आन बान शान ऊपर होगी। पुलिस अफसर ने अपनी तरफ से वह बात ही कही जो सामान्य तौर पर कहते हैं। उनको ऊपर से निर्देश मिले होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले राउंड की बातचीत तक यह तय हो जाएगा। यह ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड 26 जनवरी को होगी। पूरा देश देखेगा। दुनिया देख लेगी और हमारे गणतंत्र का मान बढ़ेगा। हालांकि किसान नेताओं ने साफ किया कि ये पुलिस अधिकारियों के साथ फहनल बैठक नहीं थी। अभी एक बैठक होना बाकी है। उस बैठक में तय होगा कि आखिरकार किसान परेड करने की इजाजत पुलिस से मिलती है या नहीं। लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक की समस्या होगी।



कृषि कानूनों को लेकर गठित समिति की हुई पहली बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित समिति किसानों और किसान संगठनों से बातचीत करेगी। समिति की मंगलवार को यहां हुई पहली बैठक में तीन सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन सदस्यों में सर्वश्री अशोक गुलाटी, अनिल घनवत और प्रमोद जोशी शामिल थे। समिति के एक सदस्य भूपिन्दर सिंह मान ने पहले ही इस समिति से अपने को अलग कर लिया था। श्री घनवत ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि समिति कृषि कानूनों का विरोध और समर्थन करने वाले किसानों एवं किसान संगठनों से बातचीत करेगी। समित राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्ड, किसान उत्पादक संगठन, सहकारिता और अन्य संबंधित पक्षों से भी चर्चा करेगी। किसान संगठनों को जल्दी ही बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा। किसान निजी तौर पर भी पोटल पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को समिति के गठन का आदेश दिया था।

गणतंत्र दिवस को लेकर 'महामंथन'

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक करीब शाम 5 बजे तक चली। गृह मंत्री यहां प्लाज्मा डोनर से मिले और एप भी लांच किया। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। गृह मंत्री 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाले जाने एलान के लिहाज से पुलिस की तैयारी का जायजा भी लिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक

टेक्नोलॉजी सेल का गठन

बैठक की शुरुआत में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा दिल्ली पुलिस बल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में निरंतर बदलाव होना चाहिए। इसके लिए पुलिस टेक्नोलॉजी सेल का गठन किया गया है जो पुलिस के कामकाज के लिए विभिन्न तकनीक के आयात, इस्तेमाल और समायोजन के लिए काम करेगा। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को बताया, दिल्ली पुलिस जांच को प्राथमिकता देते हुए लगातार विशेष उपकरण उपलब्ध करा रही है। दिल्ली पुलिस की सकारात्मक छवि बनाई गई है।

सीमा पर तनातनी के बीच

डब्ल्यूईएफ में चीनी राष्ट्रपति शी जिनिपिंग के साथ मंच साझा करेंगे मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई के महीने से ही जारी तनातनी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपिंग एक साथ मंच साझा करेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की नियमित बैठक की तुलना में इस बार यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल इस ऑनलाइन सभा के प्रबन्धकों होंगे। डब्ल्यूईएफ दवोस का मुख्य तौर पर एजेंडा दुनिया के बड़े नेताओं को एक मंच पर लाकर नई वैश्विक स्थितियों पर संबोधित करना है। जेनेवा स्थित संगठन ने कहा कि 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक होने वाले इस सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, यूरोपीयन कमिशन के प्रिंसिपेट उर्सुला वों डेर लेयेन, इटली के प्रधानमंत्री गुइडो रोतोटी भी हिस्सा लेंगे।



देश के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिक्यों और सिविल सोसाइटी लीडर्स, थीम- ए क्यूशियल इयर टू रि-बिल्ड ट्रस्ट के तहत हिस्सा लेंगे। वैश्विक नेताओं की तरफ से यह बैठक ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और पूरी दुनिया बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन क्लाउडस श्वाब ने कहा, कोविड-19 महामारी की चलते प्राथमिकताओं और फोन व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत दुनियाभर में जोरदार तरीके से महसूस की जाने लगी है।

जेईई मेन में 12वीं में 75 फीसदी अंकों की अनिवार्यता हटाई गई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। शिक्षा मंत्रालय ने जेईई मेन परीक्षा दे रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए जेईई मेन को लेकर 12वीं में 75 फीसदी अंकों की पात्रता संबंधी नियम को हटा दिया है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने यह हटाने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को टवीट कर यह घोषणा की। निशंक ने टवीट कर कहा कि आईआईटी जेईई (एडवॉंस्ड) और पिछले अकादमिक वर्ष को लेकर लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए अगले अकादमिक सत्र 2021-2022 के लिए जेईई मेन के लिए 12वीं में 75 फीसदी मार्क्स संबंधी पात्रता नियम को हटाने का फैसला किया गया है।

उत्का वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा

अरुणाचल में चीन के गांव बनाने की खबर पर बोले राहुल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव बनाने की एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि उनका वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। बता दें कि राहुल गांधी हर रोज अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं। राहुल गांधी ने पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को सरकार से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भीतर विवादास्पद क्षेत्र में सौ घरों के एक गांव का निर्माण की खबर पर जवाब मांगा था। चिदंबरम ने कहा कि यदि भाजपा सांसद के दावे सही हैं तो क्या सरकार चीन को क्लीन चिट देकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराएगी। गौरतलब है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना क्षेत्र मानता है। जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता को जवाब नहीं पता तो अपनी असफलता कबूल करनी चाहिए।

राहुल गांधी ने अपने टवीट के साथ एक हिंदी अखबार की खबर शेयर की है। इस खबर में बताया गया कि चीन ने एक साल के भीतर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के साढ़े चार किलोमीटर के भीतर सौ घरों का एक गांव बना लिया है। एक अंग्रेजी चैनल ने इसे लेकर सैटलाइट तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। इसमें एक तस्वीर अगस्त 2019 है और दूसरी तस्वीर नवंबर 2020 की है। पहली तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एक जगह पूरी तरह खाली है, जबकि नवंबर 2020 की तस्वीर में उस जगह पर कुछ ढांचे बने नजर आ रहे हैं, जिन्हें चीन का बसाया गांव बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले में इस गांव का निर्माण किया है। एलएसी से सटा यह इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है।

बजट सत्र

29 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद सत्र, एक घंटे का होगा प्रश्नकाल

सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील

नई दिल्ली ■ एजेंसी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी, लोकसभा की कार्यवाही शाम चार से रात आठ बजे तक होगी। संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी। ओम बिरला ने ये भी कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाने के प्रवृत्त



किए गए हैं। संसद के कैम्पस के भीतर 27-28 जनवरी को आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, इसमें सांसदों के परिजन और उनके स्टाफ भी टेस्ट करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों द्वारा टीकाकरण अभियान नीति को अंतिम रूप दिया गया है, ये सांसदों पर भी लागू होगा। बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और दो हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने इस बारे में सिफारिश की थी।

सांसदों को अब नहीं मिलेगी 35 रुपए की थाली, अब खाने के लिए चुकाना होगा पूरा दाम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सांसदों को अब संसद भवन परिसर की कैटिन में सैंडविच वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। ओम बिरला ने कहा कि सांसदों, अन्य को संसद में कैटिन के भोजन पर दी जाने वाली सैंडविच रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि संसद की कैटिन को अब आईटीडीसी (इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) चलाएगा। इससे पहले उत्तरी तटवे के पास ये जिम्मेदारी थी। कैटिन में एक थाली की कीमत 30 रुपए थी।



अफगानिस्तान में दो जजों की गोली मारकर हत्या

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दो महिला जजों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये हत्या किसने और किन वजहों से की है। अभी तक इस बारे में ज्यादा जानकारी निकल सामने नहीं आ पाई है। ऐसी आशंका है कि आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस इलाके में ये घटना हुई है। उसके आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। वहां पर जांच चल रही है। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई



हैं। अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग का नया चलन शुरू हो गया है। आए दिन बम धमाकों और रॉकेट हमलों से दहल जाने वाले इस देश में आतंकी अब लोगों को चुन-चुन कर मार रहे हैं।

आतंकी अब यहां भीड़ को निशाना नहीं बना रहे हैं। उनके निशाने पर नेता, वकील, जज, पुलिस और मीडिया है। कुछ दिन पहले ही टीवी पत्रकार मलाला मेवेंद और उनके ड्राइवर को गोलियों से भून दिया गया था। काबुल शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार सुबह हबीबुल्लाह नाम के जज को मार डाला। पुलिस के अनुसार यह घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे कार्त-ए-ना क्षेत्र की है और हमलावरों की तलाश की जा रही है।

अभी तक तालिबान या किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगान सरकार और सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों की यह हई चाल मुसीबत का सबब बन चुकी है। विस्फोटक से भरी कार से या फिर अज्ञात बंदूकधारी किसी न किसी को निशाना बनाने में लगे हैं।

अब तक 10 से ज्यादा पत्रकारों की मौत
अफगानिस्तान में अब तक दस से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। बीते दिनों ही पत्रकार मलाला मेवेंद को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। मलाला की हत्या के 24 घंटों के भीतर ही एक और युवा टीवी एंकर फरदीन अमीनी भी संधिस्थितियों में मृत पाए गए। पिछले महीने रेडियो आजादी के पत्रकार इत्यास डायी की कार को आईडीडी विस्फोट से उड़ा दिया गया था। नवंबर की शुरुआत में ही टोला न्यूज के सीनियर एंकर यामा सियावश की कार में बम लगाकर हत्या कर दी गई थी। उनके साथ उनके दो साथी भी मारे गए थे। अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है।

चीन में सरनेम का अकाल: 120 करोड़ लोगों के सिर्फ 100 सरनेम

काबुल। अगर आप चीन में किसी भी शब्द से उसका सरनेम पूछेंगे, तो जवाब मिलेगा- वांग, ली, झांग, लिउ या फिर चेन। यही वे 5 सरनेम हैं, जिसे चीन की 30 बिलियन या 43.3 करोड़ लोगों ने अपनाया है। इससे पता चलता है कि चीन में सरनेम का अकाल पड़ गया है। चीन के लोक सुरक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक, 2010 की जनगणना की तुलना में 86 फीसदी आबादी के बीच सिर्फ 100 सरनेम ही पसंद किए गए हैं। सीएनएन की हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन में पहले 23 हजार सरनेम चलन में थे। ये सिमटकर 6 हजार रह गए हैं। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर चेन जियावेई का कहना है कि इसके तीन अहम कारण हैं- सांस्कृतिक विविधता की कमी, भाषाई दिक्रत और डिजिटल युग में तकनीकी समस्या।

भारत में सांस्कृतिक विविधता
चेन ने अमेरिका-भारत का हवाला देते हुए बताया कि यहां सांस्कृतिक विविधता है, जबकि चीन में नस्ल या समुदायों के हिसाब से विविधता नहीं है। भाषाई कारणों से कोई भी अतिरिक्त अक्षर जोड़-घटाकर कोई नया सरनेम बना लेना चीनी भाषा में अंग्रेजी की तरह आसान नहीं है। कई लोगों ने अपने पुराने सरनेम छोड़कर इसलिए नए अपनाए हैं, ताकि डिजिटल दुनिया में वो पीछे न छूटें।

मजबूरन सरनेम बदल रहे लोग
दरअसल, चीन के सरकारी गजट के तहत कम्प्यूटर सिस्टम में चीनी भाषा के जो तरीके स्टैंडर्ड के तौर पर उपयोग में लाए गए हैं, उनके हिसाब से भाषा में फेरबदल कर बनाए गए नाम रजिस्टर नहीं हो पाते, इसलिए लोगों को मजबूरन सरनेम बदलना पड़ा। चीनी भाषा में कई कैरेक्टर हैं। इनमें से 2017 तक 32,000 कैरेक्टर डेटाबेस में शामिल किए गए, लेकिन हजारों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रजिस्टर नहीं किए जा सके। चीन में पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है, इसलिए कई सरनेम को इसमें जगह नहीं मिल पाया। जिन लोगों के सरनेम डिजिटल प्रणाली में फिट नहीं हुए, उन्हें 2013 में पुलिस ने सरनेम बदलने पर मजबूर कर दिया। प्रो. जियावेई ने कहा कि चीन में मंदारिन जैसी कई बोलियों को डिजिटल सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। कैरेक्टर स्टैंडर्ड अपनाने के कारण सरकार को क्यूआर कोड, पासवर्ड या पिन जनरेट करने में दिक्रत आ रही थी। समय लेने वाली इस प्रक्रिया से बचने के लिए बड़ी आबादी ने अपना सरनेम ही बदल लिया। हालांकि इन्हें दुख है कि उनकी पीढ़ियां अपने इतिहास, पहचान और परंपरा को भूल जाएंगी।

सिंध की पाक से आजादी की मांग

मोदी समेत सात वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर लहराए, लोग बोले- आतंकी राज में रह रहे, सिंधुदेश बनवाएं

सिंध। पाकिस्तान के सिंध के लोगों ने प्रांत की आजादी के लिए खुलकर वर्ल्ड लीडर्स से मदद मांगी है। आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक जीएम सैयद की 117वीं जयंती पर जामशेरो प्रांत में एक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों ने आजादी समर्थक नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर भी दिखाए गए।

आजादी समर्थक नारे भी लगाए

रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सिंध राज्य सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है। ब्रिटिश साम्राज्य ने यहां जबर्न कब्जा कर लिया गया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में सौंप दिया।

इन वर्ल्ड लीडर्स के पोस्टर लहराए गए

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

जो बाइडेन (प्रेसिडेंट इलेक्ट, अमेरिका)

एंटोनियो गुटेरेस (हू प्रेसिडेंट)

जेसिंडा आर्डन (प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड)

मोहम्मद बिन सलमान (क्राउन



प्रिंस, सऊदी अरब)

अशरफ गनी (राष्ट्रपति, अफगानिस्तान)

एंजेला मर्केल (जर्मन चांसलर)

बर्बर हमलों के बावजूद सिंध ने पहचान बचाई

जेई सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शाफी मुहम्मद बर्फात ने बताया कि इतिहास और संस्कृति पर सभी

बर्बर हमलों के बावजूद सिंध ने अपनी एक बहुलवादी, समकालीन, सहिष्णु और सामंजस्यपूर्ण समाज के रूप में अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है।

सिंध में विदेशी और देशी लोगों की भाषाओं और विचारों को न केवल एक-दूसरे को प्रभावित किया है, बल्कि मानव सभ्यता के सामान्य संदेश को

स्वीकार भी किया है।

पाकिस्तान के अत्याचारों से प्रताड़ित

बर्फात के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि सिंध ने भारत को अपना नाम दिया, सिंध के नागरिक, जो उद्योग, दर्शन, समुद्री नेविगेशन, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के धुरंधर थे, वे आज पाकिस्तान के फासिस्ट

आतंकियों के राज में रहने को मजबूर हैं। सिंध में कई राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो एक आजाद सिंध राष्ट्र का समर्थन करती हैं। हम अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पाकिस्तान ने हम पर कब्जा किया हुआ है। वह न केवल हमारे संसाधनों को बर्बाद कर रहा है, बल्कि यहां मानवाधिकार उल्लंघन भी हो रहा है।

1967 से चल रहा संघर्ष

सिंध को अलग देश बनाने की मांग 1967 से चल रही है। तब जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद राशिद की लीडरशिप में सिंधुदेश आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

पिछले कुछ दशकों में यहां पाकिस्तान की सिक्वोरिटी एजेंसियों ने कत्लेआम मचा रखा है। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया और मार दिया गया।

सिंध में मिली थी सिंधु घाटी की सभ्यता

1921 में सिंध के लरकाना में ही सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला था। भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने यहां खुदाई करवाई थी। सिंध में ही मोहनजोदड़ स्थित है।

भारत-नेपाल हुए एक: वैक्सीन लाई करीब, कोरोना से जंग में ओली के साथ मोदी सरकार

काठमांडू। भारत में वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही केन्द्र की मोदी सरकार ने नेपाल में कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करने वाली है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक भारत नेपाल को वैक्सीन मुहैया कराना शुरू कर सकता है। बता दें कि हाल ही नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली भारत के दौरे पर थे, इस दौरान विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और वैक्सीन की मांग की थी, जिसपर सरकार ने नेपाल को वैक्सीन देने का वादा किया था।

मोदी सरकार नेपाल को करेगी वैक्सीन की सप्लाई

भारत और नेपाल के बीच सीमा तनाव और नए मैप को लेकर जारी विवाद के बीच कोरोना संकट से निपटने की पहल पर दोनों देश एक साथ आये हैं। हाल में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली नई दिल्ली आये थे। इस दौरान भारत के प्रतिनिधि संग उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान भले ही भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के बड़े अभियान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाली विदेश मंत्री संग मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन उनके इस दौरे को काफी अहम माना गया।

नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली भारत दौरे पर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ज्ञवाली को अगवानी की। वहीं सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार ने नेपाल

की आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करने का वादा किया है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम



की ट्रेनिंग और मांड्यूल को लेकर चर्चा हुई।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय वार्ता में वैक्सीन पर चर्चा

वैसे इसके अलावा मोदी सरकार देश के अन्य पड़ोसी देशों जैसे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव को भी कोरोना वायरस

वैक्सीन सप्लाई करेगा। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की सप्लाई के बाद नेपाल के फंडलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा।



नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा

नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण के अबतक 2 लाख 67 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी में 1 हजार 954 लोगों की मौत हो चुकी है।

'कोरोना' पर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ चीन, वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने उगला राज

बीजिंग। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने चीन के वुहान शहर पहुंची विश्वन स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) के टीम के दौरे के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है।

वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने माना है कि रहस्यमय गुफाओं से चमगादड़ के नमूने लेते समय उन्हें कुछ चमगादड़ों ने काट लिया था। जिन गुफाओं से चीनी वैज्ञानिक नमूने लेने गए थे, वे गुफाएं कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ों का घर कही जाती हैं। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर करीब दो साल पहले दिखाए वीडियो में चीनी वैज्ञानिकों ने चमगादड़ के काटने की बात को स्वीकार किया है।

वीडियो के जरिये सामने आई चीनी वैज्ञानिकों की करतूत
इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ के नमूने लेते समय लापरवाही



बरती जिससे वे चमगादड़ के शिकार बने। यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है, जब डब्ल्यूएचओ की टीम कोरोना के स्रोत की जांच के लिए चीन में मौजूद है। चीन ने काफी टालमटोल के बाद जांच दल

को अपने यहां आने और वुहान में जांच करने की अनुमति दी है।

बता दें कि दुनिया भर में तबाही मचाने वाली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की शुरुआत पिछले साल चीन के वुहान शहर से हुई थी। एक साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की टीम को कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए वुहान आने दिया है।

चीन ने वीडियो को कर दिया सेंसर: यह वीडियो सबसे पहले चाइना साइंस एक्सप्लोरेशन सेंटर ने पोस्ट किया था, लेकिन बाद में उसे चीन ने सेंसर कर दिया।

चीन की बैट वूमन वीडियो में कहती सुनाई पड़ रही है कि यह काम इतना खतरनाक नहीं है जितना लोग सोचते हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि चमगादड़ में कई खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन इनके सीधे इंसान को संक्रमित करने का खतरा ज्यादा नहीं होता है।

अफगान में पत्नियों को लेकर नया आदेश जारी, एक से ज्यादा पत्नियां रखने पर पाबंदी

अफगान। अफगान में पत्नियों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। अफगानी तालिबान के मुखिया मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा ने एक आदेश जारी कर तालिबान के नेताओं और कमांडरों के एक से ज्यादा पत्नियों रखने पर पाबंदी लगा दी है। इस नए नियम पर हैबतुल्ला के अनुसार, शादियों पर ज्यादा खर्च होने की वजह से विरोधियों को उनके खिलाफ प्रोपेगैंड का मौका मिल जाता है। लेकिन अफगानिस्तान की मुस्लिम परंपरा के तहत पुरुषों को एक समय में अधिकतम चार पत्नियां रखने की इजाजत है और ये कानूनी तौर पर भी है।

पत्नियों रखने पर रोक

इस बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबानी नेताओं की तरफ से शादी के लिए फंडिंग की मांग बढ़ने लगी थी। जिसकी वजह से एक से अधिक पत्नियों रखने पर रोक का फैसला लिया गया है। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, जिन पुरुषों



के पास बच्चा नहीं है, जिन्हें अब तक बेटा नहीं हुआ है, जो विधवा से शादी करना चाहते हैं या फिर जिनके पास एक से अधिक पत्नियां रखने की आर्थिक क्षमता है, उन्हें पाबंदियों से छूट दी गई है। लेकिन इन लोगों को एक से अधिक पत्नियों रखने के लिए अपने नेता से इजाजत लेनी होगी।

साथ ही मुखिया हैबतुल्ला ने पाबंदियों को लेकर लिखित बयान जारी किया है। पत्नी रखने के इस बयान में हैबतुल्ला ने कहा है-हम इस्लामिक अमीरात के अधिकारियों को इस्लामी शरीया के मुताबिक निर्देश देते हैं कि अगर जरूरत न हो तो दूसरी, तीसरी और चौथी शादी न करें। तालिबान कमांडरों और नेताओं से अपने मातहत लोगों को भी इस निर्देश पर अमल कराने के लिए कहा गया है।

असल में अफगानिस्तान में शादियों पर बंद चढ़ कर खर्च करने की होड़ रहती है। इसके साथ ही दूल्हे को दुल्हन के घर वालों को मेहर के तौर पर मोटी यानी अच्छी-खासी

रकम देनी पड़ती है। और फिर इसके बाद एक से ज्यादा शादी करने पर हर पत्नी के लिए अलग घर का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में दुल्हन के घर वालों को 20 लाख अफगानी (करीब 19 लाख रुपये) तक देने पड़ते हैं। तालिबान नेता और कमांडर इस रकम की मांग संगठन से ही करते हैं। अब इस तरह पैसा खर्च होने से अफगान तालिबान को फंड की किल्लत का सामना करना पड़ता है।

इस बीच सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक से ज्यादा शादी न करने का फरमान जारी करने वाले अफगान तालिबान प्रमुख हैबतुल्ला ने खुद ब खुद दो शादियां कर रखी हैं। जबकि अफगान तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर की तीन पत्नियां थीं। और उमर के बाद तालिबान की कमान संभालने वाले मुल्ला अख्तर मंसूर की भी तीन पत्नियां थीं। जिसके बाद अब ये फरमान जारी किया गया है।

संपादकीय

विकास दर संभालने की कवायद

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, कोरोना महामारी की वजह से मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.7 फीसदी तक की गिरावट हो सकती है। यह गिरावट पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में विकास दर 4.2 प्रतिशत थी। वैसे तो, पहले भी जीडीपी दर ऊपर-नीचे होती रही है, लेकिन आजादी के बाद यह पहला मौका होगा, जब इसमें इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल, कोविड-19 के कारण इस वर्ष अप्रत्याशित हालात बन गए। लॉकडाउन लगाकर हमने अपनी आर्थिक गतिविधियां खुद बंद कर दीं। युद्ध के समय भी ऐसा नहीं होता। वैसी स्थिति में संघर्ष के बावजूद मांग की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उत्पादन का डांच बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था चलती रहती है। जैसे, दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी में चॉकलेट बनाने वाली एक कंपनी ने हवाई जहाज के कल-पुर्जे बनाने शुरू कर दिए। मगर कोरोना संक्रमण-काल में मांग और आपूर्ति, दोनों ठप हो गईं। अपने यहां जब कभी भी गिरावट आई, तब उसकी वजह तात्कालिक रही। मसलन, सन 1979 से पहले अर्थव्यवस्था में सिकुड़न सूखे के कारण होता था। चूंकि उस दौर में उत्पादन का प्रमुख आधार कृषि था, इसलिए साल 1951, 1965, 1966, 1971, 1972 और 1979 में पर्याप्त बारिश न होने से विकास दर प्रभावित हुई। कृषि-उत्पादन बढ़ने ही अर्थव्यवस्था अपनी गति पा लेती थी। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती थी। साल 1967-68 में यह भी पाया गया कि देश में जब सूखा आता है, तो कपड़ोंकी मांग कम हो जाती है। असल में, सूखा पड़ जाने से लोगों की क्रय-श्रमता कम हो जाती थी और वे नए कपड़े खरीदने से बचने लगते थे। चूंकि कृषि के बाद कपड़ा उद्योग दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर था, इसलिए वहां मांग कम होने का असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखता। मगर 1979-80 के बाद अर्थव्यवस्था पर सर्विस सेक्टर हावी होता गया, जिसके कारण सूखे के बावजूद अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। जैसे, साल 1987 के सूखे के बाद भी विकास दर धनात्मक रही। अब अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 13 प्रतिशत के करीब रह गई है, जबकि सर्विस सेक्टर की भागीदारी बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। इस कारण यदि कृषि में 20 फीसदी तक की गिरावट (जो काफी ज्यादा मानी जाएगी) भी आती है, तो अर्थव्यवस्था को सिर्फ 2.6 प्रतिशत का नुकसान होगा, जबकि सर्विस सेक्टर आठ प्रतिशत की दर से भी बढ़ता रहा, तो वृद्धि दर में उसका पांच फीसदी का योगदान रहेगा।

विगत वर्षों में जब कभी संकट आया, तो सरकार को खस पहल करनी पड़ी। साल 2007-08 की वैश्विक मंदी का ही उदाहरण लें। इसमें सरकार ने मांग बढ़ाने का काम किया, जिसके कारण विकास दर काबू में रही। उस समय न सिर्फ किसानों के कर्ज माफ किए गए, बल्कि अल्पकालीन, ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाकर दो-तीन लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाए गए। इससे देश का राजकोषीय घाटा जरूर बढ़ गया, लेकिन लोगों के हाथों में पैसे आने से बाजार में मांग पैदा हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे भेजने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को खूब लाभ मिलता है। इसके बरअवस, शहरी लोग रुपये की आमद होने पर विलासिता की चीजें अधिक खरीदते हैं। चूंकि विलासिता के ज्यादातर उत्पाद विदेश से आयात होते हैं, इसलिए इन पर खर्च किया जाने वाला काफी पैसा संबंधित निर्यातक देश के खाते में चला जाता है, जबकि ग्रामीण बाजार में विलासिता की चीजें तुलनात्मक रूप से कम खरीदी जाती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसों की आमद बढ़ जाती है। आंकड़ों में इस साल कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मगर पहली तिमाही में इस क्षेत्र में जबर्दस्त गिरावट आई है, क्योंकि मंडी में फल-सब्जी जैसे उत्पाद काफी कम मात्रा में पहुंचे। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था कुछ संभली जरूर, लेकिन पटरी पर नहीं लौट सकी। तीसरी-चौथी तिमाही की भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही। यानी, जो आकलन किया गया है, उससे भी ज्यादा की गिरावट आ सकती है। जैसे कि सर्विस सेक्टर में रेस्तरां, होटल, परिवहन आदि की सेहत अब भी डांबडोल ही है। इस संकट का समाधान क्या है? सार्वजनिक खर्च बढ़ाने का दांच खेला जा सकता है, पर हमारा राजकोषीय घाटा पहले से ही बढ़ा हुआ है। कोविड-19 से पहले केंद्र, राज्य और सार्वजनिक इकाइयों का संयुक्त घाटा करीब 10 फीसदी था। पिछले साल की आखिरी तिमाही में वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी, जबकि इससे दो साल पूर्व की तिमाही में आठ फीसदी। पहले से बिगड़ रही आर्थिक सेहत को कोरोना महामारी ने आईसीएम में पहुंचा दिया है। मांग और आपूर्ति खत्म हो जाने के कारण नए तरीके से इस संकट से हमें लड़ना होगा। इसलिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाना एकमात्र उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि राजकोषीय घाटा अभी 20 फीसदी से भी अधिक है। बीते साल 22 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का भी एलान किया गया। मगर इसका सिर्फ 15 फीसदी हिस्सा बजट के रूप में आवंटित किया गया, शेष 85 फीसदी राशि बैंक बॉन्ड बांटने की बात कर रहे हैं। चूंकि कर्ज लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे, इसलिए यह राशि उनकी क्रय-श्रमता नहीं बढ़ा सकी। बेहतर तो यह होता कि सरकार ग्रामीण योजनाओं के बजट बढ़ाती, ताकि लोगों के हाथों में सीधे पैसे पहुंचें। वैसे भी, संगठित क्षेत्र की कंपनियां खुद को संभाल सकती हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी भी होती है और बैंक के दरवाजे भी उनके लिए खुले रहते हैं, जबकि अपने देश में असंगठित क्षेत्र की तकरीबन छह करोड़ छोटी-मोटी इकाइयां हैं, जो बहुत छोटे, लघु और मध्यम उद्योग के 99 फीसदी रोजगार बांटती हैं। परेशानी इन्हीं छोटी को है। यहीं से लोगों का पलायन हुआ है। जाहिर है, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार जरूरी है। 100 दिनों के बजाय जरूरतमंदों को 200 दिनों का रोजगार दिया जाना चाहिए। इस समय जरूरत एक शहरी रोजगार योजना की भी है। अर्थव्यवस्था तभी संभलेगी, जब मांग बढ़ेगी। और, इसके लिए लोगों के हाथों में पैसे देने चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

आलोचना से परेशान होने वाले नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेनी चाहिए कि अपनी आलोचना कैसे सहें

यहां तक कि मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहना पड़ा कि कांग्रेसी नेता उन्हें 'गंदी नाली का कीड़ा' तक कहते हैं। क्या इससे भी अधिक मानहानि करने वाला कुछ और लज्जाजनक हो सकता है? यदि प्रधानमंत्री कार्यालय इन लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी में उलझता तो उन मुकदमों को देखने के लिए एक विभाग अलग से गठित करना पड़ता। स्पष्ट है कि भारत सहित दुनियाभर के नेताओं को विशेषकर फेसबुक-ट्विटर के इस दौर में आलोचनाओं को सहना सीखना ही होगा। खासतौर से हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों को अवश्य इस मामले में सीख लेनी चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पुष्ट करने के साथ ही अपनी आलोचना से कुपित होने वाली सरकारों को आईना भी दिखाता है। आशा की जानी चाहिए कि यह निर्णय उन अन्य राज्य सरकारों के लिए भी नजीर बनेगा जो नागरिकों द्वारा अपनी आलोचना के बाद उन्हें सताने पर आमादा हो जाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यशवंत सिंह के मामले से जुड़ा है जिन्हें खिलाफ पिछले वर्ष इस कारण एफआइआर हुई थी कि उन्होंने एक टवीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश को जंगलराज में तब्दील कर दिया है। टवीट में हत्या, अपहरण और फिरोती मांगने से जुड़े मामलों का हवाला भी दिया गया था। सिंह पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत एफआइआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 500 जहां मानहानि से जुड़ी है वहीं आईटी एक्ट की धारा 66डी का संबंध किसी की छवि विकृत कर उसके साथ धोखाधड़ी से है। इस एफआइआर के खिलाफ यशवंत सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने दलील दी कि सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही सरकार की आलोचना की और सरकारी कामकाज से ऐसी असहमति कोई अपराधिक कृत्य नहीं। ऐसे में उनके खिलाफ एफआइआर दुर्भावना से प्रेरित है जिसका मकसद उन्हें सरकार के खिलाफ असहमति प्रकट करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई अपराध ही नहीं हुआ तो एफआइआर खारिज की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता के खिलाफ

एफआइआर और अन्य कार्रवाई को खारिज करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की से किया गया। यह फैसला सरकार और पुलिस-प्रशासन के लिए बड़ा झटका है। यदि राज्य का कोई

नागरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से असंतुष्ट है तो उसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करना जिसमें दो साल तक की सजा हो सकती हो, कुछ अजीब लगता है। ऐसे में न्यायाधीशों ने सरकार की खिंचाई करके उचित किया। हालांकि यह चलन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। कई अन्य राज्यों की सरकारों और मुख्यमंत्रियों ने भी संविधानप्रद नागरिकों के इस अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है। इस सूची में बंगाल सबसे ऊपर आया। न केवल ऐसे मामलों की संख्या में, बल्कि आलोचकों को जेल भेजने की ऐसी परिपाटी भी उसने ही शुरू की। इस सिलसिले की शुरुआत ममता बनर्जी सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महापात्रा और उनके मित्र को गिरफ्तार करके हुई। उन पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

गया कि वे मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने वाले कार्डिन प्रसारित कर रहे हैं। इसके विरोध में महापात्रा ने राज्य मानवाधिकार आयोग में गृहार लगाई। आयोग ने उनकी गिरफ्तारी को गलत ठहराने के साथ ही राज्य सरकार को उन्हें एवं उनके मित्र को पचास-पचास हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश भी दिया। राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप महापात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। हाई कोर्ट ने न केवल आयोग के फैसले को सही बताया, बल्कि क्षतिपूर्ति की राशि को भी बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया।

तमिलनाडु ने तो इस मामले में हद ही कर दी थी जब वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी नीति के विरोध में एक लोक गायक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसी तरह केरल की माकपा सरकार राज्य ललित कला अकादमी के मुखिया से तब नाखुश हो गई थी जब वार्षिक अवार्ड्स के लिए उन्होंने उस कार्डिन को चुना था जो जिसका विषय दुष्कर्म के आरोपी एक पादरी पर केंद्रित था। इसी संगठनों और राज्य सरकार ने अकादमी पर इस निर्णय को लेकर पुनर्विचार के लिए दबाव बनाया, लेकिन अकादमी अपने निर्णय पर अडिग रही।

हराणी की बात यही है कि यह सब

उस देश में हो रहा है जिसके वरिष्ठ नागरिकों की स्मृति में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परिवेश के अनुभव होंगे जहां अतीत में सत्तारूढ़ लोगों के खिलाफ और भी कड़वी बातें हुआ करती थीं। बोफोर्स घोटाले के दौर में इंडियन एक्सप्रेस तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए राम जेटमलानी के दस सवाल रोजाना प्रकाशित करता था। उन तलख सवालों से राजीव गांधी विचलित अवश्य होते होंगे, लेकिन उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वास्तव में अपनी आलोचना से परेशान होने वाले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए कि वे उन्हें अपशब्द कहने वालों से कैसे निपटते हैं। मोदी विरोधी फेसबुक-ट्विटर पर उन्हें लेकर अत्यंत आपत्तिजनक सामग्री लगाते रहते हैं। कई बार असंसदीय हैशटैग बनाकर उन्हें ट्रेंड भी कराते हैं। उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर मर्यादा तक भूल जाते हैं।

यहां तक कि मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहना पड़ा कि कांग्रेसी नेता उन्हें 'गंदी नाली का कीड़ा' तक कहते हैं। क्या इससे भी अधिक मानहानि करने वाला कुछ और लज्जाजनक हो सकता है? यदि प्रधानमंत्री कार्यालय इन लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी में उलझता तो उन मुकदमों को देखने के लिए एक विभाग अलग से गठित करना पड़ता। स्पष्ट है कि भारत सहित दुनियाभर के नेताओं को विशेषकर फेसबुक-ट्विटर के इस दौर में आलोचनाओं को सहना सीखना ही होगा। खासतौर से हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों को अवश्य इस मामले में सीख लेनी चाहिए।

बड़े बेआबरू होकर

अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा देकर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग का सामना करने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 197 के मुकाबले 232 मतों से पारित कर दिया गया। खास बात यह कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के भी दस सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इसी 20 जनवरी, यानी आले बुधवार को ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले 19 जनवरी को ही संसद के ऊपरी सदन सीनेट में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत को देखते हुए प्रस्ताव का पास होना तय माना जा रहा है। पूछा जा सकता है कि सिर्फ एक दिन के लिए महाभियोग चलाने की इस कवायद का भला क्या मतलब है। इस सांकेतिक कार्रवाई से क्या हासिल होने वाला है? असल में ऐसी कार्रवाइयों को कम महत्वपूर्ण मानने का ही नतीजा हमें पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाले आर्ट-वॉश (अति-दक्षिणपंथ) के उभार के रूप में देखने को मिल रहा है।

राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही ट्रंप खुद को अमेरिकी लोकतंत्र के नियमों और संस्थाओं से ऊपर का चीज दर्शाते रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौते से वे यह कहते हुए बाहर आ गए कि यह समझौता बराक ओबामा ने किया था, जैसे ओबामा उन्हीं की तरह एक निर्वाचित राष्ट्रपति न होकर धोखे से इस पद पर काबिज हो गए हों। हाल में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद तो उन्होंने मतदाताओं के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। हर उपलब्ध मंच पर उनका दावा खारिज हो गया, फिर भी वे चुनाव में धोखाधड़ी की बात पर अड़े रहे। और फिर जिस दिन चुनाव नतीजों पर संसद की मोहर लगनी थी, उसी दिन ट्रंप समर्थकों ने संसद में घुसकर जो उत्पात मचाया, वह अमेरिकी इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय बन गया है। सबसे अहम सवाल अब यही है कि इस प्रकरण को लेकर अमेरिकी लोकतंत्र कितनी सख्ती बरतता है। दुनिया भर में लिबरल राजनीतिक धाराओं का चलन ऐसी प्रवृत्तियों से निपटने के मामले में ढीलापोली बरतने का ही रहा है। धुर दक्षिणपंथी ताकतों को हराकर सत्ता में आने के बाद ड्राइव-टोटे से बचकर राय करना ही उनकी एकमात्र प्रथाप्रक्रिया हो जाती है। यही वजह है कि ह्यूड्रबाज ताकतों द्वारा जनतांत्रिक संविधान के साथ खिलवाड़ की कोशिशें पूरी दुनिया में तेज हुई हैं। अमेरिकी संसद ने महाभियोग का फैसला लेने के क्रम में दलील सीमाओं से ऊपर उठकर यह संदेश दिया है कि देश का संवैधानिक ढांचा कोई राजनीति करने की चीज नहीं है और अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका मुकाम एक ऐसी लोकतंत्र रेखा का है, जिसे अगर राष्ट्रपति भी पार करता है तो उसे इसका दंड भुगतान होगा।

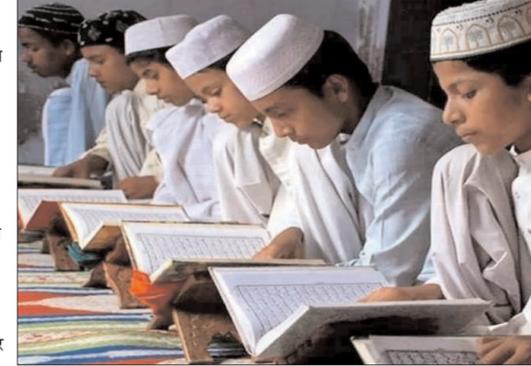
मदरसा शिक्षा में सुधार हेतु बने ठोस रणनीति, केवल धार्मिक पक्ष को न बनाया जाए मुद्दा

यह वास्तविकता है कि देश ऐसे कई उदाहरण देख चुका है, जब साधन और साध्य में उत्पन्न विरोधाभास ने कई नीतिगत फैसले को पुंगू साबित कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारंभ में जिस तरह बाध्यकारी बनाया गया, इसे लोगों ने सहजता से स्वीकार नहीं किया, जबकि बाद के वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण को मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य से जोड़कर बनाई गई नीति काफी प्रभावी साबित हो रही है। मदरसा शिक्षा में सुधार और अक्सर निरसन विधेयक, 2020 के अगर विभिन्न पक्षों की बात करें, तो कहीं न कहीं यह सरकारी मदरसा में आधुनिक शिक्षा को लागू करता है जिसमें धर्म गुरुओं की भूमिका काफी अहम होगी।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि भारत में छह लाख से अधिक निजी मदरसे चलते हैं जिसका खर्च मुस्लिम समाज 2.5 फीसद जकात की रकम से निकालते हैं। प्राइवेट मदरसे में भी काफी संख्या में गरीब मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे में यह ध्यान देना होगा कि अगर सरकार धार्मिक पक्षकारों को साथ लाने में कामयाब हो जाती है तो गरीब

मुस्लिम बच्चों को आधुनिक और कोशल युक्त शिक्षा में आधारभूत संरचना पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास में यह काफी अहम है कि भारत की इस विभिन्नता को हमें एक सकारात्मक दिशा देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। गौरतलब है कि 56 साल बाद ऐसा पहला मौका था, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह को बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस संबोधन में कई पक्षों पर चर्चा हुई, पर यहां सरोकार यह है कि ऐसे मौके ही विरोधाभास खत्म करने का अवसर प्रदान करते हैं।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमेशा से की थी। यह एक नकारात्मक पक्ष ही है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के निधन के करीब 51 बरस बाद मदरसों की शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत हो सकी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा की वार्षिक बैठक में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर एक मदरसा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी, इस तर्क के साथ कि इस तरह से मदरसे की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी सरकारी नौकरी में लाया जा सकेंगे। अतः अब जरूरत है कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक ठोस रणनीति पर काम हो।



यदि कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जोर-जबरदस्ती वाला रवैया अपनाया गया तो किसी कानून की खैर नहीं

जिसका परिचय दिल्ली-एनसीआर के लोगों की नाक में दम करने वालों ने शाहीन बाग में धरने पर बैठकर दिया था। दिल्ली आने-जाने के प्रमुख रास्तों पर किसानों के डेरा डालने से हर दिन हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसान नेता दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जानबूझकर परेशान करने का काम कर रहे और फिर भी खुद को अन्नदाता के तौर पर पेश कर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता इस बात को समझें तो बेहतर कि यह संभव नहीं कि वे लोगों को परेशान भी करें और उनकी हमदर्दी पाने की भी उम्मीद करें।

यह संभव है कि नए कृषि कानून कुछ किसानों और किसान संगठनों को रास न आ रहे हों। ऐसे किसानों और उनके संगठनों को इन कानूनों का विरोध करने और यहां तक कि उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन का भी अधिकार है। वे यह भी कह सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को खत्म करे, लेकिन उन्हें या फिर किसी अन्य को यह अधिकार नहीं कि वह रास्ते रोककर इन कानूनों को खत्म करने की जिद पकड़ ले। करीब 40 किसान संगठन ठीक यही कर रहे हैं। वे न केवल दिल्ली के विभिन्न रास्तों को अवरुद्ध किए हुए हैं, बल्कि इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे रास्तों को पूरी तरह जाम कर देंगे अथवा गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। यह और कुछ नहीं, लोगों को तंग कर सरकार को झुकाने की प्रवृत्ति है। यह एक तरह से लोगों को बंधक बनाकर सरकार से कानूनों की वापसी के रूप में फिरोती मांगने की कोशिश है। यदि सरकार इस दबाव के समक्ष झुक जाती है तो कल को कोई भी संगठन दस-बीस हजार लोगों को दिल्ली लाकर और यहां के रास्ते जाम कर यह मांग कर सकता है कि फलों कानून खत्म किया जाए। इससे तो लोकतंत्र पर भीड़तंत्र ही हावी होगा।

किसान नेता केवल कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद ही नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि सरकार से बातचीत के दौरान इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं - न अपील, न दलील, केवल रिपील। सातवें दौर की बातचीत में ठीक



यही कहा गया। शुरुआती दौर में तो यह स्थिति थी कि केंद्रीय मंत्री जैसे ही अपनी बात कहना प्रारंभ करते थे, किसान नेता कुर्सियां घुमाकर उनकी ओर पीठ करके बैठ जाते थे। अब वे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यदि संसद नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, अध्यादेश के जरिये तीनों कानूनों को वापस लेने का काम किया जाए। देश में पांच सौ से अधिक किसान संगठन हैं, लेकिन महज 40 किसान संगठन यहां जटाने में लगे हुए हैं कि वे समस्त किसानों के प्रतिनिधि हैं। यह तब है जब इस आंदोलन में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा,

राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसानों की भागीदारी है। इन किसान संगठनों के कुछ नेताओं को किसान नेता कहना भी कठिन है, जैसे कि योगेंद्र यादव। वह करीब साल भर पहले जोनयू में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलनरत थे। इसके बाद वह नारिकरता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को उकसाने में जुटे। अब वह बात रहे हैं कि देश के किसानों का नेतृत्व उनके हाथ में है। हालांकि सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान नेताओं की जिद है

कि इन कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं। जोर-जबरदस्ती केवल यहीं तक सीमित नहीं, पंजाब में इस दुष्प्रचार का सहारा लेकर रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों पर हमले शुरू कर दिए गए कि इन कानूनों से तो केवल अंबानी और अदाणी को लाभ मिलने वाला है। यह दुष्प्रचार इसके बावजूद किया जा रहा है कि न तो अंबानी और अदाणी की कंपनियां किसानों से उनका की सीधी खरीदारी करती हैं और न ही उनका अनुबंध खेती से कोई लेना-देना है। पंजाब में किसान हित की लड़ाई लड़ने के नाम पर अब तक डेढ़ हजार से अधिक मोबाइल टावरों को या तो क्षतिग्रस्त किया जा चुका है अथवा उनकी बिजली काटी जा चुकी है।

इस खुली अराजकता को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने पहले अपील जारी की और फिर चेतावनी देकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली। राज्य सरकार के ऐसे हलमूल रवैये को देखकर रिलायंस जियो को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, पंजाब भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों पर गोबर फेंका जा रहा है। एक ऐसे ही कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एब मुकदमा दर्ज किया गया तो उसे रद्द करने की मांग की गई और ऐसा न किए जाने की सूरत में सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी गई। यानी चोरी और सीनाजोरी। इससे इन्कार नहीं कि किसान अन्नदाता हैं और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी

समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन यदि इस तरह से कानूनों को वापस लेने के लिए जोर जबरदस्ती वाला रवैया अपनाया जाएगा तो फिर किसी भी कानून की खैर नहीं हो सकेगी है नए कृषि कानूनों से किसानों की सभी समस्याओं का समुचित समाधान न हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संसद से पारित कानून सड़क पर खारिज करने की जिद की जाए। सड़क पर उतरे लोग वह काम अपने हाथ में नहीं ले सकते, जो संसद या सुप्रीम कोर्ट का है। कोई भी जानता कि कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, लेकिन किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि जब सरकार इन कानूनों में संशोधन को तैयार है तब फिर उनमें फेरबदल कराने के अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या इसलिए कि इच्छा सरकार को झुकाना है?

जो भी हो, यह वही रवैया है, जिसका परिचय दिल्ली-एनसीआर के लोगों की नाक में दम करने वालों ने शाहीन बाग में धरने पर बैठकर दिया था। दिल्ली आने-जाने के प्रमुख रास्तों पर किसानों के डेरा डालने से हर दिन हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसान नेता दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जानबूझकर परेशान करने का काम कर रहे और फिर भी खुद को अन्नदाता के तौर पर पेश कर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता इस बात को समझें तो बेहतर कि यह संभव नहीं कि वे लोगों को परेशान भी करें और उनकी हमदर्दी पाने की भी उम्मीद करें।

संक्षिप्त खबर

अब विद्यालयों के प्रमुख स्थानों पर लिखा होगा चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर, जरूरत पर ले सकेंगे मदद

भूमि। कैमूर जिले के सरकारी या निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आपातकालीन स्थिति में अब सहायता के लिए शिक्षा विभाग के स्तर से एक नई पहल की गई है। इस पहल से बच्चों को किसी भी संकट के समय तत्काल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बीते दिनों जिला परिषद की हुई बैठक में इसके लिए निर्णय लिया गया। जिसमें प्रत्येक सरकारी या निजी विद्यालयों के प्रमुख स्थानों पर चाइल्ड लाइन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी प्राथमिक, मध्य सरकारी व निजी विद्यालयों में चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 प्रदर्शित किया जाएगा। यह नंबर सरकारी व निजी विद्यालयों के प्रमुख स्थानों की दीवारों पर प्रदर्शित किया जाएगा। ताकि कोई भी बच्चा संकट के समय में इसे सुगमता पूर्वक उपयोग कर सके। इस संबंध में सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सभी बीईओ को कहा गया है कि चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर के बारे में विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को जानकारी दी जाए। बता दें कि चाइल्ड लाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रयोजित आपातकालीन आउटर चौफ़ फ़ोन सेवा है जो आपातकालीन संकटग्रस्त स्थिति में बच्चों की सहायता के लिए तात्कालिक एवं दीर्घकालीन सेवा प्रदान करती है। इसके लिए चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर 1098 जारी किया गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर डीईओ सूर्यनारायण ने कहा कि विद्यालयों के प्रमुख स्थानों की दीवारों पर उक्त नंबर को प्रदर्शित करने के लिए सभी बीईओ को निर्देश दिया गया है। सभी बीईओ अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी व निजी विद्यालयों के एचएम से नंबर को प्रदर्शित कराना सुनिश्चित कराएंगे। बता दें कि विद्यालयों में चाइल्डलाइन नंबर के प्रदर्शित हो जाने से बच्चों को कंडे तरह की सुविधा होगी। बच्चों को इस नंबर के बारे में जानकारी होने पर वे किसी भी संकट के समय में प्रशासन को जानकारी देकर कोई भी सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

फोरलेन सड़क की जद में दो विद्यालय, किए जाएंगे स्थानांतरित, ग्रामीणों की बढ़ी चिंता

कटिहार। मनिहरी-साहबगंज के बीच गंगा नदी पर फोरलेन सड़क पुल तथा नारायणपुर से पूर्णिया फोरलेन सड़क निर्माण कार्य आरंभ होने से लोगों में काफी खुशी है। चिर प्रतीक्षित मांग पूरी होने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। गंगा पर पुल व फोरलेन का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू है। इधर फोरलेन की जद में फिलहाल प्रखंड के दो विद्यालयों के आ जाने से लोग सन्नते में हैं। इन विद्यालयों के भविष्य की फिक्र लोगों को होने लगी है। उक्तमित मध्य विद्यालय पागलबाड़ी व उक्तमित मध्य विद्यालय पटनी नारायणपुर इस जद में आ गया है। नारायणपुर विद्यालय परिसर का 750 वर्ग कड़ जमीन भी सड़क में आ गया है। इस 750 वर्ग कड़ में परिसर में निर्मित उक्तमित माध्यमिक विद्यालय का नव निर्मित भवन का अंश व मध्य विद्यालय के निर्मित भवन का अंश भी आ रहा है। उक्तमित मध्य विद्यालय पागलबाड़ी में वर्ग एक से आठ तक पठन पाठन होता है तथा 651 बच्चे नामांकित हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापिका माला सिन्हा सहित 12 शिक्षक शिक्षिकाएं यहां पदस्थापित हैं। विद्यालय की स्थापना 1932 में हुई है। यहां निर्मित भवन फोरलेन की जद में आ गया है। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष सह वाई सदस्य अनिल कुमार मंडल ने बताया कि फोरलेन की जद में स्थूल आ गया है। सन 1932 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। कई साल पूर्व में मिट्टी व फूस की मकान था। बाढ़ व पानी की चपेट में आ जाने के कारण विद्यालय के कई कमरागत व सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ वर्ष पूर्व विद्यालय के भवन का निर्माण हुआ है। इसमें पागलबाड़ी व कुवंपुपुर सौज के बच्चे पढ़ने आते हैं। अब फोरलेन बनने से खुशी तो है,पर विद्यालय पर संकट है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में ही एक स्थल पर जमीन चिन्हित की गई है, जिसे एसडीओ व बीडीओ मनिहरी ने भी देखा है। दूसरी उक्तमित माध्यमिक विद्यालय पटनी नारायणपुर का भी 750 वर्ग कड़ जमीन फोरलेन की जद में आ गया है। यह विद्यालय मध्य विद्यालय था, इसकी स्थापना 1911 में हुई है। शुरू के वर्षों में यह विद्यालय साबिक पटनी गांव में था। वहां गंगा कटाव के बाद कई दशकों पूर्व नारायणपुर में स्थानांतरित है। इस मध्य विद्यालय को 2011 में उक्तमित कर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया। विद्यालय में वर्ग एक से दसवीं तक की पढ़ाई होती है तथा 1400 बच्चे नामांकित हैं। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष निसार आलम ने कहा कि फोरलेन बनने से खुशी है, पर विद्यालय की 750 वर्ग कड़ जमीन भी आ गई है। इस कारण माध्यमिक विद्यालय की निर्मित भवन व मध्य विद्यालय के कुछ भवन के अंश आ गए हैं।

पंजाब में घोटाला रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बदली स्कालरशिप योजना की शर्तें

चंडीगढ़। एससी पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप में फिर से कोई घोटाला न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी नई स्कालरशिप योजना में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों को पंजाब सरकार ने मंजूर भी कर लिया है और केंद्र सरकार से वर्ष 2021-22 के लिए 563 करोड़ रुपये की राशि की मांग भी कर दी है। नई योजना के अनुसार विद्यार्थियों की कुल फीस का 60 फीसद हिस्सा केंद्र और 40 फीसद हिस्सा राज्य सरकार की ओर से खर्च करने का प्राविधान किया गया है।

केंद्र सरकार ने नई योजना में कहा है कि स्कालरशिप की राशि अब सीधे कालेजों को देने की बजाए विद्यार्थियों के खाते में जमा करवाई जाएगी। केंद्र सरकार अपना हिस्सा तब तक विद्यार्थियों के खाते में नहीं डालेगी जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से का 40 फीसद हिस्सा नहीं जमा करवाएगी।

ढाबे पर रोटी मांगी तो पहचान ली आवाज, 19 वर्ष से बिहार से लापता चाचा लुधियाना में इस हाल में मिला

लुधियाना। यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 19 वर्ष पूर्व बिहार निवासी व्यक्ति घर से लापता हो गया था। परिवार वालों ने कई जगह तलाश की, लेकिन व्यक्ति का कहीं पता नहीं चला। इसी बीच, अचानक एक व्यक्ति ने रोटी की भीख मांगी। उसकी आवाज सुन युवक को लगा जैसे वह इस आवाज को पहचानता है। दिमाग पर जोर डालने पर उसे महसूस हुआ ऐसी आवाज तो उसकी चाचा की थी। बस फिर क्या था... भिखारी से नाम-पता पूछा तो वह उसका चाचा ही निकला।



शिव पुरी निवासी सिया राम मुखिया का कहना है, हम बचपन से अपने चाचा को तलाशते आ रहे थे। वो आखिर मिला भी तो अपने गांव से 1500 किलोमीटर दूर लुधियाना में। पहली नजर में चेहरा तो पहचान में नहीं आया, हां उनकी आवाज सुनते ही पहचान गया कि वो कैलाश चाचा है। चेहरे पर बड़ी हूँ दाढ़ी और लंबे-लंबे बालों ने उनका रू-रूप ही बदल दिया था। मगर जब उनके बाल कटवाने के साथ शेर कराई गई तो वो हू-ब-हू पिता जी जैसे नजर आए। सिया राम मुखिया शिव पुरी स्थित

राणा ढाबा में तंदूरी रोटी बनाने का काम करता है। वह रविवार शाम वो ढाबे पर रोटियां सेंक रहा था। इसी दौरान भिखारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने आकर रोटी मांगी। पहले सिया राम ने उसे अनदेखा कर दिया। मगर जब उसने फिर से रोटी मांगी तो सिया राम को वो आवाज जानी-पहचानी सी लगी। उसने जब उस भिखारी से नाम पूछा। उसका नाम सुनते ही वो उठलने लग गया। वो उसका 19 साल से लापता चाचा कैलाश मुखिया (56) निकला। हालांकि कैलाश ने सिया राम को नहीं पहचाना, क्योंकि जब वह घर छोड़कर गए थे तो उस समय सिया राम महज 16 साल का था। सिया राम ने फौरन अपने छोटे भाई बजरंगी मुखिया को बुलाया। उसके बाद नूरवाला रोड पर हलवाई की दुकान पर

भाजपा के दस तथा सपा के दो प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय, महेश चंद्र शर्मा का पर्चा खारिज



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दस तथा समाजवादी पार्टी के दोनो प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को पर्चा दाखिल करने वाले निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा के पास कोई भी प्रस्तावक न होने से नामांकन पत्र खारिज हो गया है। आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है जबकि 21 जनवरी को नाम वापसी का अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी के सभी दस

प्रत्याशियों ने सोमवार को दिन में 12 बजे अपना-अपना नामांकन किया। इसके करीब एक घंटा बाद निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा ने नामांकन कर इस चुनाव में खलबली मचा दी थी। इसके बाद महेश चंद्र शर्मा के पत्रों में एक भी प्रस्तावक नहीं होने के कारण उनका पर्चा खारिज हो गया। विधान परिषद के चुनाव में 13वें प्रत्याशी के रूप में सामने आए निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा का नामांकन खारिज हो गया है। उनके पत्रों में एक भी

प्रस्तावक नहीं थे। विधान परिषद के चुनाव में मुकाबले में आने के लिए नियमानुसार कम से कम 10 विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। महेश चंद्र शर्मा का दावा था कि उनके पास अपना दल के तथा निर्दलीय विधायक हैं। जब नामांकन पत्र देखा गया तो उसके प्रस्तावकों के नाम वाला बॉक्स खाली था। विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा को दस तथा समाजवादी पार्टी को दो सीट मिलेंगी। इन सभी का अब निर्विरोध

सीएम योगी माध्यमिक स्कूलों में 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति

नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर भाजपा आज सीपीए नए मंत्रियों के नाम, इनको लेकर चर्चा पटना- बिहार भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की मुहर के बाद मंगलवार की शाम या बुधवार को अपने कोटे के नए मंत्रियों के नाम की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप देगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ दिल्ली में कैप कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बिहार भाजपा के प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ एक दौर की वार्ता हो चुकी है। मंगलवार को अंतिम निर्णय के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बिहार भाजपा के नेताओं की बैठक होगी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, बिहार भाजपा के प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय अंतिम रूप से नाम तय करेंगे। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार में दो दिन सियासी पहलामहमी रहेगी। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच सरकार में पांच-पांच महकमों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्रियों की सूकधुकी बढ़ गई है। दोनों उक्त मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि उनके पास कौन-कौन विभाग रहेगा। भाजपा ही नहीं, जदयू के मंत्रियों की भी कमबोझे यही स्थिति है। वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 13 है। शिक्षा मंत्री बनाए गए मेवालाल इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अभी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पचास लाख लोगों को रोजगार देने के अभियान में लगे योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को शाम को करीब चार बजे सरकारी आवास पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के 436 चयनितों को नियुक्ति पत्र देंगे।

राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पद पर चयनित योगी आदित्यनाथ सरकार मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसी मिशन के तहत आज भी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर सूबे के डिट्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाब देवी मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद माध्यमिक



विद्यालयों के 298 प्रवक्ता और 138 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसी मिशन के तहत आज भी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर सूबे के डिट्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री गुलाब देवी मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ

कनाडा से आयी गोरखपुर के बिजलीकर्मियों की शिकायत, कहा- रिशतत दो आधा करावा दूंगा बिल

गोरखपुर। गोरखपुर शहर के बिजलीकर्मियों की शिकायत कनाडा से आयी है। कनाडा में रहने वाले वीरेंद्र ने अधीक्षण अभियंता शहर यूसी वर्मा को फोन कर बताया है कि रामीनगर स्थित उनके मकान का 30 हजार रुपये का बिल पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक बिजलीकर्मियों 15 हजार रुपये मांग रहा है। उन्होंने अधीक्षण अभियंता से इस तरह के गिरोह का पूरी तरह खाम्ता कराने का अनुरोध किया है। अधीक्षण अभियंता ने शहर के सभी अधिशासी अभियंताओं, उपखंड अधिकारियों और अवर अभियंताओं को वाट्सएप पर संदेश भेजकर फर्जीबाड़ी से जुड़े बिजलीकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

30 हजार का बिल 15 हजार करावा दूंगा- वीरेंद्र इस समय कनाडा के ह्यूस्टन में रहते हैं। रामीनगर स्थित मकान को उन्होंने किराए पर दिया है। मकान का बिजली का बिल तीस हजार रुपये हो गया है। कुछ दिनों पहले खुद को बिजलीकर्मियों बताने वाला एक व्यक्ति वीरेंद्र के घर गया। किराएदार ने ज्यादा बिल आने की शिकायत की तो बिजलीकर्मियों ने 15 हजार रुपये में पूरा बिल खत्म कराने का प्रलोभन दिया। उसने खुद का नाम मतीन

बताया और अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि रुपये की व्यवस्था हो जाए तो फोन कर लें। किराएदार ने कनाडा में रह रहे वीरेंद्र को फोन कर पूरी जानकारी दी। बताया कि 15 हजार रुपये में पूरी बिल खत्म हो जाएगा। वीरेंद्र को शक हुआ तो उन्होंने अधीक्षण अभियंता को फोन किया। अधीक्षण अभियंता ने उन्हें बताया कि मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनता है और उसी आधार पर जमा होता है। अधीक्षण अभियंता शहर यूसी वर्मा ने बताया कि वीरेंद्र के बिल की जांच कराई जा रही है। मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनाया गया है। बिल में यदि संशोधन की गुंजाइश होगी तो उपखंड अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बिल बनाने वाले मीटर रीडर, डिस्कनेक्शन गैंग, स्मार्ट मीटर लगाने वाले, सेविदाकर्मियों, केश काउंटर पर रुपये जमा करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी आदि उपभोक्ताओं को बिल कम कराने का झांसा देने वालों से सावधान रहना चाहिए। रुपये सिर्फ केश काउंटर या आनलाइन जमा करें। ठाणों की शिकायत तत्काल बिजली निगम के अफसरों या संबंधित थाना में करें। - **यूसी वर्मा, अधीक्षण अभियंता शहर**

प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को तैनाती दी जा रही है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के मिशन रोजगार की एक नई कड़ी है।

50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य- सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन रोजगार की शुरुआत की थी। इस मिशन की शुरुआत पांच दिवसों को हुई थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है।

संकट के समय में भी रोजगार देने में आगे योगी आदित्यनाथ सरकार- योगी आदित्यनाथ सरकार संकट के समय में भी प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले चार वर्ष में चार लाख युवाओं को राजकीय विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अध्यापकों को जनपदों के एनआईसी केन्द्र में समय से उपस्थित होने को कहा गया है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 436 चयनित

आप विधायक सोमनाथ को मिली रिहाई, बोले- योगी की संविधान से आस्था खत्म हो चुकी

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली से विधायक सोमनाथ भारती जिला कारागार से मंगलवार को रिहा हो गए। रिहाई के बाद विधायक ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें जेल में डालकर अच्छा किया। जेल व्यवस्था की विफलता का अंदाजा दे देता है। यूपी में गलत देखुंगा तो बोलांगा। सरकार मुझे जेल में रखे या फांसी पर चढ़ा दे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि योगी की



संविधान से आस्था खत्म हो चुकी है। वह संवैधानिक मूल्यों को दरकिनारा कर रहे हैं। तानाशाही के जरिए विपक्षियों का मुंह बंद करना चाहते हैं। हम उनमें से नहीं हैं।

उ न क ी राजनीतिक विफलता, अस्पताल, स्कूल की बदहाली के बारे में लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हर व्यक्ति यही कह रहा है कि प्रदेश में अधोषिक्त आपातकाल लग गया है। कांग्रेस ने घोषित आपात काल लगाया था, लेकिन यह सरकार अधोषिक्त रूप से सत्यता बयान करने से रोक रही है। इसी तरह का ट्रीटमेंट विपक्षियों को देंगे

तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आंशिक रूप से पेश किया गया मेरा बयान- विवादित टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उनके बयान को आंशिक रूप से पेश किया गया है। राज्य सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के क्षेत्र प्रयागराज के एक अस्पताल में वह गए थे। वहां एक कमरे में कुत्ते के सात आठ बच्चे पैदा हुए थे। अस्पताल की व्यवस्था बेहद खराब थी। उसी की ओर मेरा इशारा था...

सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। सोमनाथ ने कहा कि रायबरेली में मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया। पुलिस की मौजूदगी में

मेरे ऊपर स्याही फेंकी गई। इसके पूर्व मुझे कमरे के बाहर मूवमेंट से रोकना था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। योगी के मौत के बयान पर उनका कहना था कि उन्होंने उनके कार्यशैली को लेकर राजनीतिक मौत की बात कही थी। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। बताते चले कि आप विधायक पर बीते दस जनवरी को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। विधायक 11 जनवरी को अमेठी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 15

चिराग पासवान को बिहार में लगता है उर, सीएम नीतीश के हनुमान ने पूछ- आप आते हैं कब है जनाव

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष-विपक्ष में हिंदुस्तानी अवाग मोर्चा के अध्यक्ष जीवनराम मांडवी तथा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान फिर आमने-सामने हो गए हैं। इस बार मामला कानून-व्यवस्था का मुद्दा है। इधर कुछ समय के दौरान कई बड़ी आपराधिक वारदातों को लेकर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अब डर लगता है। यहां चर्चित व बड़े लोग भी सुरक्षित नहीं रहे। स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कदम उठाने चाहिए। इसपर पलटवार करते हुए राजनीति में नीतीश कुमार के हनुमान माने जाने वाले जीवनराम मांडवी ने कहा कि चिराग बिहार आते ही कब है कि उन्हें डर लगता है

बिहार की कानून-व्यवस्था को भयावह बताते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अब तो यहां डर लगता है। राज्य में आत तो आम, बड़े लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गुहमंत्रों भी हैं। उन्हें कानून-व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान के इस हमले पर राजनीति में नीतीश के हनुमान बनकर उभरे जीवनराम मांडवी ने पलटवार किया है। उन्होंने चिराग पूछा है कि उन्हें भला डर क्यों लगता है वे बिहार आते हैं कब है कि उन्हें डर लगता है मांडवी ने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने न केवल नीतीश कुमार के पक्ष में जनादेश दिया, बल्कि चिराग को उनकी औकात भी बता दी है।

मांडवी को मिली है नीतीश कुमार के हनुमान की संज्ञा विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जीवन राम मांडवी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि वे एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। इसके बाद उन्होंने समय-समय पर नीतीश कुमार के विरोधियों पर पलटवार किया है। विधानसभा चुनाव के दौर में भी उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध करते पर चिराग पासवान पर जमकर वार किया था। इस कारण राजनीतिक गलियारे में उन्हें नीतीश कुमार के हनुमान की संज्ञा दी गई है।

स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज देने का काम होगा तेज, 22 को डेढ़ लाख कर्मियों को लगेगा टीका

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश में बड़े अभियान के साथ चल रहे उत्तर प्रदेश में मोर्चा लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने का काम अब और तेजी से होगा। प्रदेश भर में अब 1.50 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 22 जनवरी यानी शुक्रवार को कोरोना का टीका लगाया जाएगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर टीकाकरण के डेढ़ हजार सेशन होंगे। प्रत्येक सेशन में सी-सी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। अगले हफ्ते से प्रत्येक चरण पर शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल नौ लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को हुई थी और 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया था। अभी 22,643 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगाए हैं, अब आगे हूटें हुए और बचे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश टीकाकरण के अगले चरण की तैयारियों में जुट गया है। अभी तीन दिनों का प्लान तैयार किया गया है। इसमें साढ़े चार लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कवर किया जाएगा। फिर आगे समीक्षा कर आगे के चरण निर्धारित किए जाएंगे। प्रदेश में अभी तक 10.75 लाख कोरोना वैक्सीन केंद्र से मिली है। इस वैक्सीन में से 10.55 लाख कोविशील्ड है और 20 हजार कोवैक्सीन है। वहीं इसमें से करीब 50 हजार वैक्सीन सेना और अर्द्ध सैनिक बलों को भी दी गई है। शुक्रवार को जिन डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ को टीका लगाया जाना है, उन्हें जल्द एसएमएस भेजा जाएगा। कोविन पोर्टल पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण पहले से ही कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पहले चरण के तहत अगले तीन सप्ताह में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगा दी जाए। इसके साथ ही दूसरे चरण की सभी तैयारियां समय से पूरी कर लें। योगी

ने एक बार फिर आगाह किया है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्कता बरतनी होगी।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोकभवन में टीम-11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का काम सप्ताह में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को किया जाना है। पहले चरण के तहत अगले तीन सप्ताह में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग जाए। 15 फरवरी, 2021 से पहले चरण वालों को वैक्सीन की दूसरी डोज देना शुरू कर दें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिदिन कम से कम 1.50 लाख जांच अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा अयोग्य मेलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मेलों में आयुष्यान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की जानकारी लोगों को दी जाए। सभी पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं के गोल्डन कार्ड भी वितरित करें।

हर गरीब को मिलेगा संबल योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने 10,285 हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की 224 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि



मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का वितरण किया।

आशुतोष अवस्थी आदि उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2024 तक कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सबकी पक्की छत होगी। साथ ही हर घर में नल से पानी दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि समाज में जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उसका मध्यप्रदेश सरकार सबसे पहले ध्यान रखती है। सरकार हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई-लिखाई तथा दवाई का इंतजाम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए चार श्रमोद्य विद्यालय संचालित हैं। शिक्षा विस्तार की दृष्टि से प्रदेश में और श्रमोद्य विद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संसाधनों पर देना बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने योजना को दोबारा चालू किया है तथा प्रत्येक गरीब का योजना में पंजीयन किया जाकर, लाभ दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संबल योजना के 10 हजार 285 हितग्राहियों को 224 करोड़ 08 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल लिफ्ट के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की। कार्यक्रम में श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, सांसद वीडी शर्मा, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव और श्रमायुक्त

सबका अधिकार है। हम सभी गरीबों को उनके अधिकार दिलाएंगे। जो अधिक कमते हैं उनसे टैक्स लेंगे और जिनके पास नहीं है उन्हें सहायता करेंगे। **संबल, सरकार और शिवराज आपके साथ हैं:** मुख्यमंत्री ने बैतुल जिले की श्रीमती मुमताज बानो से संवाद के दौरान कहा कि संबल, सरकार और शिवराज आपके साथ हैं। मुमताज ने बताया कि अनुग्रह राशि के दो लाख रुपए से वे बकरी पालन तथा किराने की दुकान करेगी। उनके पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी।

हम हर संकट में आपके साथ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जबलपुर की श्रीमती राशि देवरिया, बड़वाह की श्रीमती यशोदा बाई कुशवाह एवं उज्जैन की श्रीमती ममता सिकरवार से संवाद के दौरान कहा कि वे अपने को अकेला न समझें। हम हर संकट में आपके साथ हैं। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। संबल से मिली राशि का सदुपयोग करें। बच्चों को पढ़ाए।

सबसे संवेदनशील योजना है संबल: श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की सबसे संवेदनशील योजना है संबल योजना। योजना से अभी तक प्रदेश में एक लाख 80 हजार हितग्राहियों को 1483 करोड़ रुपए का हितलाभ वितरित किया गया है। योजना में 1 लाख 92 हजार प्रवासी मजदूरों का भी पंजीयन कर उन्हें लाभ दिया जा रहा है।

प्रत्येक राज्य में योजना की सराहना: वीडी शर्मा: सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि संबल योजना प्रदेश में गरीबों का संबल बन गई है। इस योजना की प्रत्येक राज्य में सराहना हो रही है। कोविड संकट के दौरान भी निरंतर गरीबों को योजना का लाभ मिला। मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। सरकार ने अभी तक गरीबों एवं किसानों के खातों में 82 हजार करोड़ रुपए की राशि डाली है।

बेटियों के पूजन से शुभारंभ: कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटियों के पूजन के साथ किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश गान हुआ।

ऊर्जा मंत्री तोमर की तरह अन्य मंत्री भी रहें अपडेट

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली की बचत, किसान सहित विभिन्न श्रेणी के हितग्राहियों और विद्युत उपभोक्ताओं के हित में उठाए गए कदम और नवाचारों को अपनाया सराहनीय है। श्री चौहान ने मंगलवार को यहां कैबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान ये निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुधार के प्रयास निरंतर हो और गुजरता में हुए कार्य को मॉडल मानकर आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग में लाइनमैन से लेकर विभिन्न श्रेणी के अभियंताओं का दायित्व निश्चित किया जाए। विद्युत चोरी रोकने से लेकर उपभोक्ताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की योजनाओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की योजनाओं का अध्ययन कर अपडेट रहने की दिशा में श्री तोमर सक्रिय रहें हैं। अन्य मंत्री भी ऐसा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने की ऊर्जा विभाग के कार्यों की सराहना

बड़े बकायादारों से सख्ती से करें वसूली

श्री चौहान ने कहा कि विद्युत देयक के बड़े बकायादारों से बकाया राशि की नियमित वसूली की जाए। कोई रियायत न हो। राजस्व वृद्धि के लिए सख्ती से बकाया राशि की वसूली की जाए। इससे निर्धन उपभोक्ताओं के हित में योजनाओं के अमल में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग यह अध्ययन करे कि ऐसे उपभोक्ताओं को अयकरदाता है, वे योजनाओं में ससिडी का फिना लम ले रहे हैं। बड़े बकायादारों को अनावश्यक कट नही मिले और गरीबों को आवश्यक रियायत जरूर प्राप्त होती रहे।

राजस्व बढ़ाने के प्रयास जारी: बैठक में जानकारी दी गई कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा राजस्व वृद्धि के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही वाणिज्यिक नुकसान कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाना प्रस्तावित है। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि बकायादारों से माह दिसंबर-2019 में कुल 1723 करोड़ वसूल किए गए थे। वर्ष 2020 के दिसंबर माह में यह वसूली 1948 करोड़ हुई है, जो 225 करोड़ रुपए अधिक है।

भविष्य की ऊर्जा है सौर ऊर्जा: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा है। इस दिशा में तेजी से प्रयास बढ़ाए जाएं। प्रेजेंटेशन में कुसुम योजना के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। इस योजना में किसानों को संपूर्ण कृषि फीडर से संबद्ध कर नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसान को न सिर्फ प्राई बिजली मिलेगी बल्कि विद्युत उत्पादन के लिए राशि के भुगतान की व्यवस्था भी रहेगी। योजना में 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कुसुम-1 और कुसुम-3 योजनाओं के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में इनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई।

जल जीवन मिशन के कार्य की गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मिशन के माध्यम से तीन वर्षों में घर-घर नल के माध्यम से सीधे पानी पहुंचाया जाना है। मिशन के क्रियान्वयन में कार्य की गुणवत्ता एवं जनता के फीडबैक पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री चौहान मंगलवार को यहां मंत्रालय में मध्यप्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की बैठक ले रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव आईसीपी के शशी, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव और प्रमुख सचिव मनोज गोविंद आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'फीडबैक' केवल सरकारी न हो अपितु दो-तीन अन्य माध्यमों से लिया जाना चाहिए। समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रदेश में काफी कार्य हुआ है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र छूट गए हैं, उन सभी को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कर कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में प्रदेश में तीव्र गति से कार्य हुआ है। गत जून माह में मिशन का कार्य प्रदेश में चालू हुआ और हम आज देश में तीसरे स्थान पर हैं। इसमें देश में नंबर-एक होने के प्रयास किए जाएं। बैठक में जल निगम के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, एक महिला निदेशक की नियुक्ति आदि निर्णय भी लिए गए।

मुख्यमंत्री ने संचालक मंडल की बैठक में दिए निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों से चर्चा के दौरान कहा

आमजन तक पहुंचे विभागों के श्रेष्ठ कार्यों और नवाचारों की जानकारी

मंत्रिगण अपने विभाग संबंधी एक विशेष आइडिया सुझाएं

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अनेक विभाग जनकल्याण से जुड़े श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। अनेक नवाचार अपनाए गए हैं। इनकी जानकारी आमजन तक पहुंचे इसके लिए मंत्रिगण नेतृत्व करते हुए ऐसी गतिविधियों से अवगत करवाएं। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रीपरिषद के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि अच्छे कामों का विवरण प्राप्त कर अन्य विभाग और व्यक्ति भी इस दिशा में प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिगण अपने विभाग से संबंधित एक विशेष नवाचार या कार्य का आइडिया भी प्रस्तुत करें। हम नीति निर्माता हैं। मंत्रियों को विभाग की गतिविधियों के साथ ही शासन की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी भी रहे तो श्रेयस्कर होगा। अन्य विभागों के कार्यों से भी मंत्री अवगत रहें। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत आइडिया के संबंध में विचार-विमर्श कर निर्णय भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में रिकार्ड तोड़ गेहूँ खरीदी हुई थी। मध्यप्रदेश, देश में सर्वाधिक उपाजर्न वाला राज्य बना। इसी तरह धान की खरीदी भी ऐतिहासिक रही। मप्र का किसान संतुष्ट है। किसानों को समय पर राशि का भुगतान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान के उपाजर्न का कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। मंत्रिगण भी बधाई के पात्र हैं।



प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं को समाप्त करके ही हम चैन की सांस लेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं को पूरी तरह कुचलना है। मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतें दु:ख और दुर्भाग्य का विषय हैं। शासन ने शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, जो जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तरह के माफियाओं को पूरी तरह समाप्त करके ही हम चैन की सांस लेंगे। समय-समय पर कम्प्लेक्स और आईजी स्तर के अधिकारियों से संवाद कर प्रदेश में विभिन्न तरह के माफिया और मिलावटियों के विरुद्ध अभियान की प्रगति की जानकारी ली जा रही है।

तबादले होंगे, लेकिन युक्तिसंगत

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण नीति पर विचार करेंगे। नीति ऐसी होगी जो युक्ति संगत रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक से 30 अपील तक स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाया जाएगा। सिर्फ अप्रैल माह में वेन हटाएंगे। मानवीय और प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा। इसके बाद वर्ष भर स्थानांतरण नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक विभाग समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर लें।

प्रदेश में आज लगे रोजगार मेले

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि जमा की जा रही है। पिछले महीने में भी कोरोना संकट के समय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाया गया। इस क्रम में बुधवार, 20 जनवरी को प्रदेश में रोजगार मेले लग रहे हैं। इन मेलों में सभी मंत्री सहभागिता करें। युवाओं को रोजगार दिखाने के उद्देश्य से यह राज्य सरकार की टोस पहल है।

रेत माफियाओं के विरुद्ध करें कड़ी कार्रवाई: पटेल

भोपाल (एजेंसी)। हरदा खिलाफ सख्त कदम उठाने के जिले की हडिया तहसील में रेत के तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन के आला अफसरों और पुलिस अधीक्षक से फोन पर चर्चा कर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में अवैध रेत खनन के

कृषि मंत्री ने तेज रफ्तार डंपर से हुई बाइक सवार की मौत पर बताया दुख

गौरतलब है कि हडिया की मोहनपुरा खदान से तेज रफ्तार डंपर निकलने से हादसे की आशंका बनी रहती है, मृतक युवक हडिया का ही रहने वाला बताया जा रहा है। कृषि मंत्री पटेल ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

मध्यप्रदेश में हो रहा संसदीय विद्यापीठ का निर्माण

प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से भेंट कर दी जानकारी

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित रहे।

श्री शर्मा ने भेंट के दौरान नवंबर 2019 के वडिया में हुए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सफल आयोजन की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केवडिया के विकास एवं उनके दूरदर्शी सोच पर चर्चा हुई। श्री शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश में पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के भवन निर्माण हेतु विधानसभा परिसर के अंतर्गत दो एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है जिसका निर्माण प्रस्तावित है। शर्मा ने बताया कि संवैधानिक संस्थाओं में सफलता पूर्वक कार्य संपादित हो सके इस पवित्र उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे जी के नाम से संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई है। इसके साथ ही श्री शर्मा ने विधायक विश्राम गृह निर्माण निर्माण की जानकारी श्री बिरला को दी।



है जिसका निर्माण प्रस्तावित है। शर्मा ने बताया कि संवैधानिक संस्थाओं में सफलता पूर्वक कार्य संपादित हो सके इस पवित्र उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे जी के नाम से संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई है। इसके साथ ही श्री शर्मा ने विधायक विश्राम गृह निर्माण निर्माण की जानकारी श्री बिरला को दी।

मध्य भारत में मील का पत्थर साबित होगा विद्यापीठ: बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि निश्चित रूप से संसदीय विद्यापीठ के माध्यम से संसदीय परंपराओं को बढ़ाने उनके महत्व के प्रचार-प्रसार से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर परिषद, विधानसभा हो या विधान परिषद इनका सुचारु और सफल संचालन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मध्य भारत में यह विद्यापीठ निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसदीय विद्यापीठ के निर्माण एवं संचालन में हरसंभव मदद करने के लिए आवश्यक है, साथ ही उन्होंने भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यापीठ का निर्माण शासन एवं विधानमंडल से किया जाए, परंतु लोकतंत्र की मर्यादाओं एवं परंपराओं के लिए यह बेहतर होगा कि विद्यापीठ का संचालन एवं संवर्धन विधानमंडल द्वारा ही किया जाए। जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं पोषण मिलता रहे।

इनका कहना है

केंद्रीय आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में सुधार कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा, इसलिए सभी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के मौजूदा हालात पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई भी होगी। **वैद्य राजेश कोटेश,** केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयुर्वेद कॉलेजों में गुणात्मक सुधार लाना बेहतर कदम है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय है कि आयुर्वेद कॉलेज, विश्व में प्रमाणिकता के साथ विकसित हों। इस दिशा में टोस कदम उठाए जाएंगे, जिसका लाभ भविष्य में छात्रों को भी मिलेगा। विदेशी छात्र भारत में और भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ सकेंगे। **डॉ.राजेश पांडे,** राष्ट्रीय प्रवक्ता, आयुर्वेद आयुष मेडिकल एसोसिएशन

शिक्षा समाचार

चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर हुई चर्चा



भोपाल। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सागर ने मंगलवार को यहां मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में संचालित पैरामेडिकल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स के रूप में संचालित किए जाने के संबंध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम के बाद फेलोशिप प्रोग्राम प्रारंभ करने के संबंध में भी चिंतन किया गया। फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर्स को विशिष्ट चिकित्साकौशल ट्रेनिंग प्रदान करना है। फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के साथ ड्रग ट्रायल और रिसर्च को बढ़ाने के मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग के साथ समन्वय करने का निर्णय लिया गया है। श्री सागर ने कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) से चिकित्साकौशल सेवाओं को सुदृढ़ बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात चिकित्सकों को चिकित्साकौशल सेवाएं प्रदान करने का आवश्यकता है। साथ ही मेडिकल कॉलेज द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में मेडिकल कैंप का आयोजन हो। इसमें निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स, अस्पताल, चिकित्सा संगठनों एवं एनजीओ को जोड़ा जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, आयुक्त निरांत बरबई और संचालक डॉ. उल्का श्रीवास्तव उपस्थित थीं।



कृषि मंत्री से मिले माधव सिंह और गोविंद मालू

भोपाल। प्रदेश के किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल से मंगलवार को यहां मंडी बोर्ड के मुख्यालय कक्ष में बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष माधव सिंह दांगी के साथ भाजपा नेता गोविंद मालू की सौजन्य भेंट की। इस दौरान उनकी विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक संदीप यादव मौजूद थे।

मुरैना में किसान महापंचायत आज

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमिटी बुधवार, 20 जनवरी को मुरैना में विशाल किसान महापंचायत आयोजित करेगी। इस किसान महापंचायत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्रभाष शंखर ने मंगलवार को यहां बताया कि बुधवार को मुरैना में आयोजित किसान महापंचायत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश चवरी, कालीलाल भुरिया, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवर, पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, सख्त कोरेगों के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, पूर्व सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायक, कांग्रेस पक्ष के सभी स्तर के जनप्रतिनिधि, किसान, कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। श्री शंखर ने बताया कि कांग्रेस इस आयोजन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से किसानों के लिए बनाए गए तीन काले कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों के हित में निर्णय लिए जाने की मांग का पुरजोर समर्थन करेगी। श्री शंखर ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीन काले कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों द्वारा देश भर में चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता बताते हुए यह बात दोहराई कि किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का निरंतर समर्थन जारी रहेगा।

राजामाता विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगा महिला मोर्चा

भोपाल। भाजपा की वरिष्ठ नेता राजमाता स्व. विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि (25 जनवरी) पर भाजपा महिला मोर्चा बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगा। महिला मोर्चा की बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। स्व. राजामाता जी की पुण्यतिथि पर महिला मोर्चा द्वारा किए जाने वाले आयोजनों को लेकर मोर्चा की बैठक मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया द्वारा 25 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गयी। साथ ही सभी जिला एवं मंडल अध्यक्षों को बूथ स्तर तक स्व. राजामाता की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में निर्देशित किया गया। बैठक में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह, महामंत्री भगवन्तलाल सबनीनी, कविता पाटीदार ने उपस्थित मोर्चा पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक में सुष्मा जैन, सरिता देशपांडे, शशि सिन्हा, बिल्किस जहां, शिवमणि मारण, भावना सिंह सहित मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष हंसकुंवर राजपूत ने किया एवं आभार महामंत्री सविता यादव ने मना।

आयुर्वेद कॉलेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कवायद

प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजों की पड़ताल करेंगे केंद्रीय आयुष सचिव

भोपाल (एजेंसी)।

प्रदेश के आयुर्वेद कॉलेजों की जांच-पड़ताल करने के केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेश और उनका दल जल्दी ही मप्र आ सकता है। केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित अस्पतालों में नियमों का कितना पालन हो रहा है और कॉलेजों का मौजूदा स्तर क्या है, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्रीय आयुष सचिव श्री वैद्य का दौरा जानकारी बिना सार्वजनिक किए होगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित अस्पतालों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सभी कॉलेजों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर कॉलेजों में सुधार किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने साल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद कॉलेज तैयार करने की योजना बनाई है। योजना को अमलीजामा पहनाने की मंशा से सबसे पहले कॉलेजों के वर्तमान हालात देखे जाएंगे। **लापरवाही कर रहे कॉलेजों पर होगी कार्रवाई:** केंद्रीय आयुष सचिव श्री कोटेश बिना पूर्व जानकारी



दिए, किसी भी कॉलेज में जाकर वहां के हालात देखेंगे। वे और उनके दल की रिपोर्ट के आधार लापरवाही कर रहे कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कमियां मिलने पर पहले कॉलेज प्रबंधकों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, अगर सचिव कोटेश और उनका दल कॉलेज प्राबंधकों की बात से संतुष्ट होते हैं, तो सुधार का मौका दिया जाएगा।

फरवरी-मार्च में तैयार होगी रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार फरवरी-मार्च में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार होगी। इसकी तैयारी केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने शुरू कर दी है। कॉलेज संचालन के नियम और जानकारी से संबंधित दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। कॉलेजों से कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे और सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट बनाई जाएगी।

2021 की सबसे बिजी ऐक्ट्रेस होंगी दीपिका पादुकोण

इस बात में कोई शक नहीं है कि दीपिका पादुकोण बॉलिवुड की बेहतरीन ऐक्ट्रेस में से एक हैं। यही वजह है कि इन दिनों उनकी झोली में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2021 उनके फिल्मी करियर का सबसे व्यस्त साल होगा। दीपिका के 6 प्रोजेक्ट्स पहले ही अनाउंस हो चुके हैं और अब फैंस अपनी फेवरिट ऐक्ट्रेस को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दीपिका जिन्होंने हाल ही में रितिक रोशन के साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट फाइटर का अनाउंसमेंट किया था, के पास इंटरस्टिंग प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट है।

शाहरुख और प्रभास के साथ मिली फिल्म

जहां वह सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ शकुन बत्रा की अनाम फिल्म की शूटिंग में बिजी थीं, उन्हें शाहरुख खान के साथ पतन में भी रोल ऑफर हो गया। इसके अलावा दीपिका को नाग अश्विन की फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट भी कास्ट कर लिया गया। वह द इंटरन की हिंदी रीमेक और महाभारत में भी नजर आएंगी।

शूट्स के लिए करेंगी प्री-प्लानिंग

ऐक्ट्रेस के करीबी एक स्रोत ने बताया, ये सभी फिल्मों इसी साल नहीं फिल्माई जाएंगी लेकिन दीपिका पूरे साल कम से कम दो प्रोजेक्ट्स की शूटिंग करेंगी। यही नहीं, वह बाद के फिल्म

मेरा सफर खास रहा है

अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने साल 2014 में आई फिल्म 'फुगली' से बॉलिवुड में कदम रखा था, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। इसके बाद कियारा 'एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी', 'लस्ट स्टोरीज', 'कबीर सिंह' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों में नजर आईं। कियारा के लिए उनकी कोई एक खास भूमिका उनके लिए गेमचेंजर साबित नहीं हुई है बल्कि वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी सभी फिल्मों को देती हैं। कियारा ने बताया, 'मेरे लिए हर एक फिल्म मायने रखती है। मेरी पहली फिल्म ने मुझे इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका दिया। लोग अधिकतर 'कबीर सिंह' और 'लस्ट स्टोरीज' का जिक्र करते हैं, लेकिन हर फिल्म का अपना एक महत्व है, जिसमें मेरी आने वाली फिल्मों में शामिल हैं इसलिए मैं सिर्फ किसी एक फिल्म को सारा श्रेय नहीं देना चाहती। मेरे लिए मेरा अब तक का पूरा सफर ही खास रहा है।' आने वाले समय में अभिनेत्री अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'इंदू की जवानी' की एक स्ट्रिंग में नजर आएंगी। वह सिद्धार्थ मल्होत्रा संग 'शेरशाह' में भी दिखाई देंगी। इसके अलावा, कियारा 'भूल भुलैया' और 'जुग जुग जियो' का भी हिस्सा है।

लंबे समय बाद सिनेमाघर पहुंचे इमरान हाशमी

बॉलिवुड अभिनेता इमरान हाशमी सिनेमाघर में वापस आ गए हैं। अभिनेता ने एक इंस्टाग्राम तस्वीर साझा की, जहां वह सिनेमाघर में फिल्म देखते नजर आ रहे हैं। शोयर तस्वीर में अभिनेता सिनेमाघर में सबसे पीछे सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं, वहीं एक अन्य तस्वीर में वह खड़े होकर पोज मार रहे हैं। सिनेमाघर में अभिनेता ने मास्क नहीं पहना है, जिसके एवज में वह इसके पीछे का कारण भी बताया है। शोयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, उन जादुई अंधेरे कमरों की ओर, जिन्हें थिएटर कहा जाता है। आपमें से कुछ सोच रहे होंगे की मैंने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो आपको बता दें हमने सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया हुआ है। इमरान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह कर्फ्यू फ्री, मास्क फ्री वर्ल्ड चाहते हैं। इमरान वर्तमान में जय कृष्णन द्वारा निर्देशित एक अलौकिक हॉरर फिल्म एजा के लिए शहर में शूटिंग कर रहे हैं। अभिनेता को अमिताभ बच्चन के साथ सस्पेंस ड्रामा वेहर में देखा जाएगा। रूमी जाफरी के निर्देशन में रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ कपूर, क्रिस्टेल डिसूजा, रघुवीर यादव और अनू कपूर भी हैं।

जब सलमान खान एक लड़की से नहीं कर पाए थे प्यार का इजहार

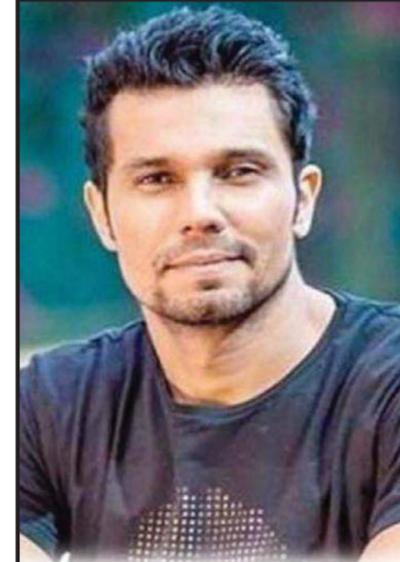
बॉलिवुड एक्टर सलमान खान 55 साल की उम्र में कुंवारे हैं। फैंस अक्सर उनसे यही पूछते हैं कि आखिर वह कब शादी करेंगे। हालांकि, सलमान को प्यार तो हुआ है, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। सलमान खान ने एक बार बताया था कि वह एक लड़की को पसंद करते थे, लेकिन रिजेशन के डर से उन्होंने उस लड़की के सामने अपने प्यार का कभी इजहार नहीं किया। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इस बात का बिचकुल भी पछतावा नहीं है।

दरअसल, सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में अजय देवगन और काजोल में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान ने बताया कि उन्हें एक लड़की बहुत पसंद थी। शो में काजोल, सलमान से पूछती हैं, क्या आपको कभी कोई पसंद आई हो और आपने उसे नहीं बताया इसके जवाब में सलमान ने कहा, जी हां पसंद आई थी लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। उस वक्त उनके कूते ने मुझे काट लिया था। यह बात सुनकर अजय देवगन बोले- तो अभी बता दो अब उसका पति काटेगा। सलमान ने कहा, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं वह मुझे रिजेंट न कर दे इसलिए नहीं बताया। सलमान ने आगे बताया कि 15 साल पहले मैं उनसे मिला था और भगवान का शुक है कि मैंने उन्हें बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे तीन दोस्त थे जिनका अलग-अलग टाइम में उनसे अफेयर था। मुझे यह बात तब पता चली जब वह मुझे पसंद करने लगी थी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तब वह ग्रांडमदर बन चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पोते आपके फैंस हैं। वे आपकी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। सलमान ने बताया कि उन्हें इस बात का बिचकुल भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने उन्हें पसंद करने वाली बात नहीं बताई। उन्होंने इसका कारण भी शोयर किया। सलमान ने कहा कि अगर मैं उनसे शादी कर लेता तो मैं भी ग्रांडफादर बन गया होता।



जाह्नवी कपूर ने कॉलेज के दिनों की डरावनी डेट का किया खुलासा

कोरोना महामारी के बीच आमजनों की तरह बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने-अपने काम पर लौट आए हैं। ऐसे में सेलेब्स से जुड़े कई कहानी-किस्से, शोबेक फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं, सेलेब्स भी चैट शो में शामिल होकर अपने एक्सपीरियंस शोयर कर रहे हैं और पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने कॉलेज के दिनों को याद किया और कुछ डरावनी बातों को शोयर किया। जाह्नवी ने एक इंटरव्यू में अपने डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात की। उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी डेटिंग लाइफ के डरावने वक्त के बारे में बताया, जिन्हें याद कर वे आज भी सहम जाती हैं। जाह्नवी ने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह एक डेट पर गई थीं और वो एक्सपीरियंस उनके लिए काफी खराब था। उन्होंने बताया, मैं डेट नहीं करती। मैं डेट्स पर बाहर जाना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है आखिरी बार जब मैंने यह किया था तब मैं लॉस एंजलिस में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। जाह्नवी ने इस डेट को एक डरावना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा- वो गलत था। उसने मुझे कुछ गलत ही कहा था। जाह्नवी ने बताया कि अगर वह किसी को पसंद करती हैं तो कभी भी खुद उसकी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाती हैं। वे इस मामले में बहुत शर्मीली हैं इसलिए वह कोशिश करती हैं कि सामने वाले के लिए हिंट छोड़ दें। जाह्नवी ने कहा कि उन्हें सामने वाले में दिलचस्पी है ये बात वह तब तक सामने नहीं आने देती हैं जब तक उन्हें ये साफ नहीं हो जाता है कि सामने वाला भी उनके बारे में यही सोचता है। उन्हें आंखों-आंखों में बातें करना पसंद है। बता दें कि जाह्नवी कुछ दिनों पहले कार्तिक आर्यन के साथ शूटिंग में बिजी थीं। दोनों फिल्म दोस्ताना-2 में साथ काम करते नजर आएंगे। दोनों ने बीते दिनों गोवा में साथ में छुटियां मनाई थीं और इसके बाद इस बात के ज्यादा कयास लगने शुरू हो गए कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।



इंस्पेक्टर के रोल में नजर आएंगे रणदीप

बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा अपनी फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेता के लिए फिल्म में काम करना काफी रोमांचित और चुनौतीपूर्ण रहा है। रणदीप अपनी पहली वेब-सीरीज फिल्म 'इंस्पेक्टर अविनाश' की शूटिंग कर रहे हैं, जो एक पुलिस थ्रिलर है जो पुलिस अधिकारी अविनाश मिश्रा के जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने शुक्रवार को श्रृंखला की शूटिंग शुरू की। रणदीप ने कहा, 'अविनाश मिश्रा जैसे रोमान्टिक और चुनौतीपूर्ण है। मैं इस सीरीज के साथ वर्ष की शुरुआत करने के लिए रोमांचित हूँ और इसके साथ दर्शकों के लिए पूरी तरह से मनोरंजन प्रेश करने के लिए उत्सुक हूँ।' नीरज पाठक द्वारा निर्देशित यह शो उत्तर प्रदेश में सेट है। अभिनेता का पुलिस अवतार उसे राज्य में अपराधिक गतिविधियों से निपटने वाले प्रसिद्ध पुलिस के जीवन की एक नाटकीय रिटेलिंग में एक्शन में देखेगा। पुलिस थ्रिलर जियो स्टूडियो और गोल्ड मार्टेन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है।



मैं अब भी अपने क्षेत्र की शीर्ष अभिनेत्री मानी जाती हूँ

बांग्ला फिल्मों की सुपरस्टार रितुपर्णा सेनगुप्ता आगामी फिल्म सॉल्ट के साथ हिंदी जगत में लौट रही हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ने फिल्म में चंदन रॉय सान्याल के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है। अपनी हालिया फिल्म के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, साल्ट फिल्म एक जोड़ी के बारे में एक बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसमें महिला एक कलाकार रहती है और पति एक इंजीनियर है। फिल्म की कहानी कुछ वर्षों को कवर करती है, इन वर्षों के दौरान वे दुनिया से काफी कुछ सीखते हैं और एक-दूसरे के पास वापस आते हैं। रितुपर्णा ने प्रभात रॉय की 1992 की हिट फिल्म श्वेत पाथोरें थाला से बड़े पर्दे पर शुरुआत की थी। उन्होंने पिछले दशकों में बॉलीवुड में काम किया है। वह 1994 में रिलीज हुई फिल्म तीसरा कौन में पहली बार हिंदी स्क्रीन पर नजर आई थीं और तब से उन्होंने 30 से अधिक बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया। रितुपर्णा ने कहा, शुरु में लोगों की नजर मुझ पर हुआ करती थी और वे एक बड़े पूल में उतरना चाहते थे। वही महत्वाकांक्षी रवैया मेरे अंदर भी थी। मुझे भी राष्ट्रीय पहचान की आकांक्षा थी। हालांकि, मुझे अपने करियर में बहुत पहले ही राष्ट्रीय उपस्थिति मिल गई और धीरे-धीरे मुझे अपने क्षेत्रीय फिल्म उद्योग से प्यार हो गया। मुझे अपने क्षेत्रीय उद्योग में अपने काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। रितुपर्णा के लिए बंगाल की एक अभिनेत्री के रूप में पहचान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि मेरा क्षेत्रीय उद्योग फलता-फूलता रहे। मैं इससे बहुत जुड़ गई और इसके लिए प्रतिबद्ध हो गई। मुझे लगा कि मेरी कुछ जिम्मेदारी है, और यह मेरे कंधों पर था कि मैं मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँ। वहीं उनसे पूछे जाने पर कि, क्या उनके मन में कभी कोई असुरक्षा की भावना जगी इस पर अभिनेत्री ने कहा, मेरा स्वभाव आशावादी रहा है। मैं संकीर्ण सोच वाली महिला नहीं हूँ। मैंने वास्तव में खुद को इतने काम में डुबो लिया है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी असुरक्षा महसूस होगी। मैं अभी भी अपने क्षेत्र की शीर्ष अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हूँ, लेकिन इससे मुझे कभी अहंकार नहीं हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ।



भारतीय टीम ने तोड़ा ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड, ब्रिसबेन में रच दिया इतिहास

ब्रिसबेन, एजेंसी। युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (91), टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा (56) और प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (नाबाद 89) की करिश्माई बल्लेबाजी से भारत ने ब्रिसबेन के गाबा मैदान में ऑस्ट्रेलिया को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें दिन मंगलवार को तीन विकेट से हराकर नया इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार ब्रिसबेन में टेस्ट जीत हासिल की और चार मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत कर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। भारत को इस मुकाम के जीतने के लिए 328 रन का लक्ष्य मिला था। भारत ने सुबह जब बिना कोई विकेट खोए चार रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत चौथी पारी में इतने मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर लेगा। भारतीय बल्लेबाजों ने आखिर में वो करिश्मा कर दिखाया जिसका करोड़ों देशवासियों को इंजाम था। भारत ने 97 ओवर में सात विकेट पर 329 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत



इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। चेतन शर्मा की अगुआई में नई चयन समिति ने मंगलवार को खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही अगली सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चयन कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपनी मेजबानी में 5 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड सीरीज के पहले दो मैचों के लिए 18 सदस्यीय दल में कप्तान विराट कोहली, इशांत शर्मा और हार्दिक पंड्या की वापसी हुई, जबकि अल्लरउंडर अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट में डेब्यू करने वाले टी नटराजन को स्कॉट में जगह नहीं मिली है। खराब प्रदर्शन के चलते सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शं का भी टीम से छुड़ी हो गई है। भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली पितृत्व अवकाश (पैटर्नलिटी लीव) से, जबकि तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने चोट से उबरने के बाद वापसी की है।

दज्ज की। भारत की गाबा मैदान में सात टेस्ट मैचों में पांच हारे थे और एक ड्रॉ टेस्ट मैचों में यह पहली जीत है। भारत खेला था। गाबा मैदान में भारत की ने इस मैदान पर अपने पिछले छह ऐतिहासिक जीत के तीन बड़े हीरो रहे

शुभमन, पुजारा और पंत ने मैच के अंतिम दिन ऐसी बल्लेबाजी की जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पंत

सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बने

ब्रिसबेन, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में भारत की जीत के नायकों में रह ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकार्ड तोड़ दिया और वह सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किये थे। पंत ने चौथे टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन यह रन पूरे किये। वह 89 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने यह श्रृंखला 2.1 से जीती। इससे पहले सिडनी में तीसरे टेस्ट में भी पंत ने 97 रन की पारी खेली थी जिसे भार ने ड्रॉ कराया था। इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं।

को प्लेयर ऑफ द मैच और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला।

तेंदुलकर, गांगुली की अगुवाई में खेल जगत ने भारतीय टीम की तारीफ की

नई दिल्ली, एजेंसी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और बीसीसीआई अध्यक्ष सोरब गांगुली की अगुवाई में खेल जगत ने ऑस्ट्रेलिया में जच्चे और धैर्य का अनूठा प्रदर्शन कर चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम करने वाली भारतीय टीम की तारीफ की। भारतीय टीम एडीलेड श्रृंखला के पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली और कई अन्य अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में शानदार वापसी करते हुए ब्रिसबेन में चौथे टेस्ट में तीन विकेट की जीत के साथ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखने में सफल रही। तेंदुलकर ने कहा कि टीम को हर सत्र में नया नायक मिला। उन्होंने टि्वटर पर लिखा, हर बार जब हमारे हौसले को ठेस पहुंची, हमने संघर्ष किया टक्कर दी। हमने निडर लेकिन बेपरवाही से नहीं, क्रिकेट खेलने का आत्मविश्वास दिखाया।



“तेंदुलकर ने कहा कि टीम को हर सत्र में नया नायक मिला। उन्होंने टि्वटर पर लिखा, हर बार जब हमारे हौसले को ठेस पहुंची, हमने संघर्ष किया टक्कर दी। हमने निडर लेकिन बेपरवाही से नहीं, क्रिकेट खेलने का आत्मविश्वास दिखाया।”

जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। बीसीसीआई ने टीम को पांच करोड़ रुपए का बोनस देने की घोषणा की। यह जीत किसी कीमत से परे है। दौरे पर गये सभी खिलाड़ियों ने शानदार अजिंक्य राहणे की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, श्रृंखला में टीम इंडिया की लिए ऐतिहासिक जीत। गिल और पंत जैसे युवाओं ने तब प्रदर्शन किया जब इसकी सबसे

ज्यादा जरूरत थी। रवि शास्त्री और सहयोगी स्टाफ की मेहनत को मेरा सलाम। इस टीम पर गर्व है, ऐसे लंबे समय में एक बार होता है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, राहणे ने टीम का शानदार नेतृत्व किया। युवाओं को काफी आत्मविश्वास दिया और पुजारा ने एक बार फिर अपना जुझारूपन दिखाया। युवा गेंदबाजी आक्रमण का भी शानदार योगदान। चोट के कारण ब्रिसबेन टेस्ट के अंतिम 11 से बाहर से रविचंद्रन अश्विन ने टि्वटर पर लिखा, माफी चाहता हूँ कि यहाँ नहीं खेल सका लेकिन हमारी मेजबानी और कुछ मुश्किल क्रिकेट के लिए शुक्रिया।

संक्षिप्त खबरें

ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए पहुंचे दो खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव

मेलबर्न, एजेंसी। साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिये यहां पहुंचे दो खिलाड़ी कोरोना वायरस वायरस से संक्रमित पाये गये। इस खिलाड़ियों के बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं दी गयी है। वायरस से जुड़े नौ मामलों के कारण 72 खिलाड़ी यहां पहुंचने के बाद पहले से कड़े पुथकवास में हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि इस वायरस से प्रभावित होने वाले खिलाड़ियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हो सकती है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कड़े पुथकवास में चल रहे हैं 72 खिलाड़ियों की सूची प्रदान करने से इनकार कर दिया। कई खिलाड़ियों ने हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी स्थिति के बारे में बताया। अगले महीने आठ फरवरी को शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 1200 से ज्यादा लोग यहां पहुंचे हैं जिसमें खिलाड़ियों और कोचों के अलावा अधिकारी और मीडिया के लोग शामिल हैं। ये सभी 17 चार्टर्ड विमान से यहां पहुंचे हैं।

इब्राहिमोविच के दो गोल से मिलान ने कैंगलियारी को हराया

कैंगलियारी (इटली), एजेंसी। जाल्टन इब्राहिमोविच के दो गोल की मदद से एर्सी मिलान ने आखिरी हाफ में दस खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद इटालियन फुटबॉल लीग सेरी ए के एक मैच में कैंगलियारी को 2-0 से हराया। इब्राहिमोविच ने सातवें मिनट में ही पेनल्टी को गोल में बदला और फिर 52वें मिनट में दूसरा गोल किया। हाल में चोट से वापसी करने के बाद इब्राहिमोविच ने पहली बार गोल दागे। वह आठ लीग मैचों में अभी तक 12 गोल कर चुके हैं। एर्सी मिलान के स्थानापन्न खिलाड़ी अलेक्सिस सीलमेकर्स को 74वें मिनट में दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा था। इस जीत से एर्सी मिलान के 18 मैचों में 43 अंक हो गये हैं और वह दूसरे स्थान पर काब्रिन इंटर मिलान से तीन अंक आगे हो गया है। इन दोनों टीमों के बीच 21 फरवरी को मैच होगा।

वायरस के मामलों के बावजूद नहीं बदलेगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन का प्रारूप

मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के टूर्नामेंट निदेशक क्रैग टिले ने प्रतियोगिता से जुड़ी उड़ानों में कोविड-19 के तीन नये मामले मिलने के बावजूद सत्र के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के प्रारूप में बदलाव से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अभी अन्य ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों की तरह पुरुषों के लिये पांच सेट (बेस्ट ऑफ फाइव) और महिलाओं के लिये तीन सेट (बेस्ट ऑफ थ्री) के मुकामले होते हैं लेकिन कोविड-19 के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास का मौका नहीं मिल रहा है और इसलिए पुरुष वर्ग के प्रारूप में बदलाव की मांग उठ रही है। टिले ने हालांकि मंगलवार को नाइन नेटवर्क टेलीविजन पर कुछ पुरुष खिलाड़ियों की उमंग के लिये भी बेस्ट ऑफ थ्री सेट करने की मांग को नकार दिया। उन्होंने कहा, यह ग्रैंडस्लैम है। अभी हम पुराने प्रारूप पर ही कायम हैं जिसमें पुरुषों को पांच में से तीन और महिलाओं को तीन में से दो सेट जीतने होते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने लॉकडाउन में मुश्किल परिस्थितियों का बखान करने के लिये सोशल मीडिया का सहारा लिया है। अभी 72 खिलाड़ियों को कड़े पुथकवास में रखा गया है क्योंकि वे जिन उड़ानों से मेलबर्न पहुंचे थे उनमें कोरोना वायरस के कुल मिलाकर नौ मामले मिले थे। खिलाड़ियों के लिये अच्छी खबर यह है कि इनमें से कुछ को 14 दिनों के पुथकवास से पहले अपने कमरों से बाहर निकलने और अभ्यास करने की अनुमति मिल सकती है।

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने पिछड़ने के बाद चिली को 4-2 से हराया

सैंटियागो (चिली), एजेंसी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आखिरी नौ मिनट में तीन गोल कर यहां चिली को 4-2 से शिकस्त दी। भारत की जीत में गगनदीप (51वें और 59वें मिनट) के दो गोल के अलावा मुन्ताज (21वें मिनट) और संगीता कुमारी (53वें मिनट) का योगदान रहा। चिली के लिए अमंडा मार्टिनेज (चौथे मिनट) डोमिंगा लुडेस (41वें मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। चिली को मार्टिनेज के मैच के चौथे मिनट में पेनल्टी कानर पर गोलकर बढ़त दिला दी। भारतीय टीम ने भी जवाबी हमला जारी रखा जिसे 21वें मिनट में पहली सफलता मिली। मुन्ताज ने शानदार मैदान गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद मध्यांतर तक दोनों टीमों गोल करने में नाकाम रही। तीसरे क्वार्टर में चिली ने आक्रमण रूख अपनाया और 31वें मिनट में टीम को पेनल्टी कानर मिला। भारतीय टीम ने हालांकि बढ़त लेने की उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। मैच के 41 मिनट में हालांकि डोमिंगा ने चिली की बढ़त को 2-1 कर दी। भारतीय टीम ने हालांकि आखिरी क्वार्टर में शानदार खेल का प्रदर्शन कर मैच को अपने नाम कर लिया।

इस जीत को शब्दों में पिरोना मुश्किल : राहणे

ब्रिसबेन, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा रखे गए 328 रनों के लक्ष्य के बाद भारत की जीत की उम्मीद नहीं थी लेकिन युवा कंधों ने टीम की जीत की जिम्मेदारी ली और भारत के खतों में ऐतिहासिक जीत डाली। इसी के साथ भारत ने चार मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम करते हुए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास ही रखी है। भारत को इस जीत की इबारत शुभमन गिल (91) और ऋषभ पंत (नाबाद 89) ने लिखी। टीम की इस जीत से कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य राहणे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा है कि इस जीत को बर्ना करना मुश्किल है। राहणे ने मैच के बाद कहा, यह जीत काफी महत्व रखती है। मुझे नहीं पता कि इस जीत को कैसे बर्ना करें। मुझे अपनी टीम के खिलाड़ियों पर गर्व है, हर किसी पर। हम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ



देना चाहते थे परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने गया था तो मेरे और चेतेश्वर पुजारा के बीच यही बात हो रही थी कि पुजारा को सामान्य बल्लेबाजी करनी है और मुझे अपने शॉट्स खेलने हैं क्योंकि हम जानते थे कि आगे पंत और मयंक हैं। पुजारा को श्रेय देना होगा। उन्होंने जिस तरह से दबाव का सामना किया वो शानदार है। अंत में पंत ने भी बेहतरीन काम किया।

अश्विन मैच का हिस्सा नहीं फिर भी पत्नी प्रीति सोशल मीडिया पर कर रही कॉमेंट्री

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भले ही ब्रिसबेन के गाबा में जारी चौथे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं हैं लेकिन उनकी पत्नी प्रीति लगातार कॉमेंट्री कर रही हैं। हालांकि यह कॉमेंट्री टीवी या रेडियो पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर चल रही है। प्रीति अश्विन ने टि्वटर पर 15 जनवरी यानी मैच के पहले दिन से ही कॉमेंट्री शुरू की थी, अब वह 5वें दिन तक भी इसे बढ़ा रही हैं। इस बीच उन्होंने अपनी बेटी की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वह ध्यान लगाकर टीवी पर मैच देखती नजर आ रही हैं। उन्होंने पेसर मोहम्मद सिराज को लेकर सोमवार को भी एक ट्वीट किया था, जब उन्होंने टेस्ट करियर में पहली बार 5 विकेट हासिल किया थे।

रवि शास्त्री बोले- 36 रनों पर सिमटने के बाद इससे बढ़कर कुछ नहीं

ब्रिसबेन, एजेंसी। भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने फिटनेस समस्याओं से जूझ रही अपनी टीम की ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट सीरीज में जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि एडिलेड में टेस्ट क्रिकेट में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर सिमटने के बाद यह सपना सच होने जैसा है। शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे को अपना अब तक का सबसे खराब दौर बताया। उन्होंने कहा कि यह सबसे कठिन दौर था। इससे बढ़कर कुछ नहीं। 36 रन पर आउट होने के बाद यह

ऑबमेयांग ने दिलायी आर्सनल को शानदार जीत

लंदन, एजेंसी। आर्सनल के कप्तान पियरे एमरिक ऑबमेयांग ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में एक महीने से भी अधिक समय बाद गोल दाग जिससे उनकी टीम न्यूकास्टल के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज करने में सफल रही। ऑबमेयांग ने 16 दिसंबर के बाद लीग में कोई गोल नहीं किया था लेकिन न्यूकास्टल के खिलाफ उन्होंने दो गोल दागे। पहला हाफ गोलरहित स्कोर के बाद ऑबमेयांग ने 50वें मिनट में पहला गोल किया। बुकाया साका ने 61वें मिनट में टीम की बढ़त दुगुनी की जबकि ऑबमेयांग ने 77वें मिनट में न्यूकास्टल की रक्षापट्टि की गलती का फायदा उठाकर अपना दूसरा गोल किया। आर्सनल की सभी प्रतियोगिताओं में लगातार पांचवें मैच में बिना गोल खाये जीत दर्ज की।

मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल : पंत

ब्रिसबेन, एजेंसी। गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में नाबाद 89 रनों की पारी खेल भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा है कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा पल है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रनों की चुनौती रखी थी, जिसे भारत ने मैच के अंतिम दिन मंगलवार को सात विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंत को उनकी बेहतरीन पारी के लिए पैट कमिंस दे मैच चुना गया। पंत ने कहा, यह मेरे जीवन का अभी तक सबसे बड़ा पल है। मैं इस बात से खुश हूँ कि सपोर्ट स्टाफ और मेरी टीम के सभी साथियों ने तब मेरा साथ दिया जब मैं खेल नहीं रहा था। यह सपने जैसी सीरीज रही है। उन्होंने कहा, टीम प्रबंधन ने हमेशा मेरा साथ दिया और हमेशा कहा कि आप मैच विजेता खिलाड़ी हो और आपका टीम के लिए मैच जीतने हैं। मैं हर दिन सोचता रहता था कि मुझे भारत के लिए मैच जीतने हैं



और यह मैंने आज किया। भारत ने इस जीत के साथ चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम करते हुए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास ही रखी है।

शेन वॉर्न ने उठाए नाथन लायन की रणनीति पर सवाल



रिसबेन, एजेंसी। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन की रणनीति से काफी निराश नजर आ रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा के खिलाफ लायन की रक्षात्मक रणनीति से वॉर्न खुश नहीं थे। वॉर्न ने अपनी नाराजगी जताते हुए फील्ड प्लेसमेंट पर सवाल उठाए। वॉर्न ने कहा कि ऑफ-साइड पर बैट-पैड फील्डर लगाना चाहिए था। वॉर्न ने पांचवें दिन के पहले सेशन में कॉमेंट्री के दौरान लायन की लाइन को लेकर बात कही। नाथन लायन के पहले ही

ओवर में पुजारा एलबीडब्ल्यू आउट होते-होते बचे थे। हालांकि उसके बाद पुजारा आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने अपने कदम इस्तेमाल किए और लायन को कामयाबी हासिल नहीं करने दी। वॉर्न ने कॉमेंट्री के दौरान कहा कि उन्होंने लायन ने करीबी फील्डर के बारे में बात की थी और ऑफ-स्पिनर ने इस पर सहमति जताई थी कि पुजारा के खिलाफ यह रणनीति काम करती है। वॉर्न ने कहा, 'मैं बहुत हैरान हूँ...

मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सदमे में हूँ, इस बात का कोई तुक नहीं है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर उन्होंने करीबी फील्डर क्यों नहीं रखा है जबकि वह जानते हैं कि इससे पुजारा को अपना खेल बदलना पड़ता है, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि मुझे स्पिन बॉलिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और मैंने लायन से इस बारे में बात की थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।'

भारतीय फुटबाल टीम की नई किट लॉन्च

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय पुरुष और महिला फुटबाल टीम की नई आधिकारिक किट को मंगलवार को यहां लॉन्च किया गया। ये नई किट सीनियर महिला और पुरुष फुटबाल टीम के साथ साथ जूनियर महिला और पुरुष फुटबाल टीम के लिए भी है। दिल्ली की स्पोर्ट्स वीयर कंपनी सिक्स5सिक्स ने इसके लिए अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के साथ करार किया है। एक बयान में कहा गया है कि नई किट को पैथेरा टाइग्रिस का नाम दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय टीम के ब्लू टाइगर्स की पहचान को पुष्टा

करता है। किट में बाघ की धारियों को मूल रूप दिया गया है, जोकि गर्व, साहस और शक्ति का प्रतीक है। एआईएफएफ के महासचिव कुशल दास ने कहा, यह इतना प्रतीकात्मक है कि नए साल में राष्ट्रीय टीम की किट का शुभारंभ हो रहा है। पैथेरा टाइग्रिस भावना का प्रतीक है और कभी भी भारतीय राष्ट्रीय टीमों के सीनियर स्तर और आयु-समूहों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के प्रति मर मिटने वाले रवैये को दिखाता है। हम अपने किट प्रायोजकों को लेकर सभी समर्थन के लिए सिक्स5सिक्स का शुक्रिया अदा करते हैं।